आज का विचार

तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में तब पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर।

दैनिक सिटी दर्पण

आईना सच का

2

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़ । मंगलवार, 10 जून, 2025 वर्ष 23, अंक 142, मूल्यः 3 रुपए, पृष्ठ 8 RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 www.citydarpan.com

सीईसी ज्ञानेश कुमार अंतरराष्ट्रीय आईडिया स्टॉकहोम में मुख्य भाषण देंगे

सीईसी ने स्वीडन में भारतीय प्रवासियों के साथ यादगार बातचीत की

संवाददाता

चंडीगढ़/मोहाली

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार, जो 10-12 जून 2025 तक आयोजित होने वाले चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय आईडिया स्टॉकहोम सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वीडन की यात्रा पर हैं, ने स्वीडन में भारतीय प्रवासियों के साथ यादगार बातचीत की। सीईसी ने अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और भारत के विदेशी नागरिकों (ओसीआई) के बीच समावेशी भागीदारी और नागरिक जुड़ाव पर चुनाव आयोग के फोकस को दोहराया। उन्होंने ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण प्रणाली और डाक मतपत्र प्रबंधन प्रणाली (ईटीपीबीएमएस) के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन जैसी पहलों पर प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य विदेशी मतदाताओं की अधिक भागीदारी को सक्षम बनाना है। चुनाव प्रबंधन में भारत के नेतृत्व को रेखांकित करते हुए, श्री ज्ञानेश कुमार को कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में उद्घाटन मुख्य भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया है। भारतीय चुनावों का विशाल स्तर और इस अभ्यास में शामिल रसद की विशालता दुनिया भर के चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमबी) के बीच गहरी दिलचस्पी दिखाती है। सम्मेलन में लगभग 50 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिसका आयोजन स्वीडिश विदेश मंत्रालय, स्वीडिश चुनाव प्राधिकरण और ऑस्ट्रेलियाई चुनाव आयोग के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव सहायता संस्थान (अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए) द्वारा किया जा रहा है।

सीईसी आज अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए के महासचिव श्री केविन कैसस-जमोरा सहित अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपनी बैठकें शुरू करेंगे। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, मैक्सिको, मंगोलिया और स्विटजरलैंड सहित लगभग 20 देशों के मुख्य चुनाव आयुक्तों के साथ विस्तृत एक-से-एक द्विपक्षीय बैठकें होंगी, जो आने वाले दिनों में वैश्विक लोकतांत्रिक सहयोग और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के लिए भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेंगी। अन्य लोगों के अलावा, श्री ज्ञानेश कुमार अन्य वरिष्ठ अंतरराष्ट्रीय समकक्षों के साथ भी बातचीत करेंगे, जिनमें सुश्री लीना रिक्किला तमांग, निदेशक (एशिया-प्रशांत), अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए; डॉ. एल्सी टी. न्धिकेम्बुआ, नामीबिया के चुनाव आयोग की अध्यक्ष; और श्री अब्दुल रहमान मोहम्मद इरफान, मॉरीशस के चुनाव आयुक्त शामिल हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन चुनावी अखंडता के लिए समकालीन चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए ईएमबी के प्रमुखों, नीति निमार्ताओं और संस्थागत नेताओं को एक साथ लाता है। मुख्य फोकस क्षेत्रों में गलत सूचना, डिजिटल व्यवधान, चुनावी सुरक्षा, जलवायु संबंधी जोखिम और चुनावों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका शामिल है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए के साथ दीर्घकालिक साझेदारी बनाए रखी है, जो अपने संस्थागत नवाचारों और लोकतांत्रिक अनुभवों के माध्यम से वैश्विक चर्चा में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और सम्मेलनों के माध्यम से, भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान, क्क्क्ट भी चुनाव प्रबंधन उत्कृष्टता के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में उभर रहा है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं जिसमें क्क्क्ट के महानिदेशक श्री राकेश वर्मा, श्री विजय कुमार पांडे, उप महानिदेशक (कानून) और श्री राहुल शर्मा, प्रमुख सचिव सहित चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

सोनीपत महानगर क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को दिया गया बढ़ावा: नायब सैनी

मुख्यमंत्री ने सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की

भूपेंद्र शर्मा

चंडीगढ़

हरियाणा मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण (एसएमडीए) की आयोजित बैठक में सोनीपत महानगर क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 349.8 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई। बैठक में हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, सोनीपत के सांसद श्री सतपाल ब्रह्मचारी, विधायक श्री निखिल मदान, श्री देवेन्द्र कादियान और श्रीमती कृष्ण गहलावत और मेयर श्री राजीव जैन भी उपस्थित थे। प्राधिकरण की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगर निगम सोनीपत के नए भवन का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने कार्यों के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण का कार्यालय नगर निगम भवन बनने के बाद उसमें स्थानांतरित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नई योजनाओं और परियोजनाओं की योजना क्षेत्र की अनुमानित आबादी को ध्यान में रखकर बनाई जाए, ताकि विकास कार्यों से लोगों को अधिकतम लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि ठेकेदार तय समय सीमा के भीतर विकास कार्य पूरा करें और ऐसा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक में प्राधिकरण ने सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में एक एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) की स्थापना एवं निगरानी को मंजूरी प्रदान की। आईसीसीसी सोनीपत जैसे बढ़ते शहर में शहरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं के प्रबंधन के लिए एक केंद्रीय तंत्रिका केंद्र के रूप में काम करेगा। आईसीसीसी के प्रमुख घटकों में शहर-व्यापी निगरानी प्रणाली, स्मार्ट पार्कों और स्मार्ट सड़कों के लिए आईसीटी बुनियादी ढांचा, एक अनुकूलनीय यातायात नियंत्रण प्रणाली, यातायात प्रवर्तन प्रणाली, परिवर्तनशील संदेश संकेत, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग, एक आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली और एक सार्वजनिक संबोधन प्रणाली शामिल हैं। खाद्य क्षेत्र और उद्योगों में शहर के तेजी से विकास को देखते हुए, प्राधिकरण ने दीनबंधु छोटू राम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीसीआरयूएसटी), मुरथल में 3 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को एसबीआर (सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर) प्रौद्योगिकी पर आधारित 7.5 एमएलडी क्षमता वाले प्लांट में अपग्रेड करने को मंजूरी दी, जिसकी अनुमानित लागत 15.75 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, यमुना नदी के पास बेघा गांव से गन्नौर शहर तक 10 एमएलडी रैनी वेल और राइजिंग मेन के निर्माण के लिए 35.50 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना को भी मंजूरी दी गई। इस परियोजना का उद्देश्य गन्नौर और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को बढ़ाना है। बच्चों को खेलने के लिए, परिवारों को आपस में मिलने-जुलने के लिए तथा बुजुर्गों को आराम करने के लिए एक तरोताजा वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से, सोनीपत के सेक्टर-4 में स्टेडियम के पीछे एक नया थीम-आधारित वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया जाएगा।

नए जिलों के गठन को लेकर बनी कमेटी की रिपोर्ट मिलते ही सरकार लेगी निर्णय : सैनी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नए जिलों के गठन को लेकर बनी कमेटी प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर रही है और जैसे ही समिति की रिपोर्ट आएगी, सरकार उस पर निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर हिसार से चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट सेवा के शुभारंभ अवसर पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। नायब सिंह सैनी ने देश की सुरक्षा का जिक्र करते हुए कहा कि आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त जवाब देता है। उन्होंने उरी, पुलवामा और हाल ही की पहलगाम जैसी घटनाओं के बाद भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में की गई सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करता है, जिससे देशवासियों का आत्मविश्वास मजबूत हुआ है। जातिगत सर्वेक्षण से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई रुकावट नहीं है और प्रक्रिया निर्धारित प्रणाली के अनुसार आगे बढ़ रही है।

गांवों में प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए हम शासन को गांवों के करीब ला रहे हैं: मान

लोगों को तहसीलों में व्याप्त भ्रष्टाचारपूर्ण व्यवस्था से मिली मुक्ति

संवाददाता

दूधन साधां (पटियाला)

आम लोगों की सुविधा के लिए एक और नागरिक-केंद्रित पहल के तहत पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने आज यहां 10.80 करोड़ रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक तहसील कॉम्प्लेक्स को जनता को समर्पित किया।

एस.डी.एम., तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य अधिकारियों के कार्यालयों वाली इस इमारत को जनता को समर्पित करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का शिलान्यास जनवरी 2023 में किया गया था और इसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट समयबद्ध तरीके से नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करके लोगों को बहुत लाभ पहुंचाएगा और साथ ही यह लोगों को उनके नजदीक प्रशासनिक सेवाएं प्राप्त करने की सुविधा देगा, जिससे उनका समय, पैसा और ऊर्जा बचेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि दूधन साधां मुख्य रूप से एक ग्रामीण क्षेत्र है और पहले एस.डी.एम. का कार्यालय मिनी सचिवालय, पटियाला में स्थित था, जिसके कारण लोगों को अपने दैनिक प्रशासनिक कार्यों के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मुख्य मंत्री ने कहा कि अब आम लोगों की सुविधा के लिए राज्य

मुख्य मंत्री भगवंत मान ने 10.80 करोड़ रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक तहसील कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन

सरकार ने इस कॉम्प्लेक्स को यहीं बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि लोगों की सुविधा के लिए पूरे राज्य में ऐसे आधुनिक तहसील कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि पिछली सरकारों ने लोगों की बेहतर सेवा के लिए ऐसे प्रयासों पर कभी ध्यान नहीं दिया।

मुख्य मंत्री ने अफसोस जताया कि पहले राज्य की सत्ता गलत हाथों में थी, जिसके कारण राज्य को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि जब से हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला है, तब से सरकार ने जनहित के ऐसे कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ऐसी इमारतें लोगों की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं।

गैरजिम्मेदाराना विपक्ष का रोल निभा रहे हैं राहुल गांधी: जेपी नड्डा

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऑपरेशन सिंदूर पर की गई टिप्पणियों को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला है। नड्डा ने कहा कि वे (राहुल) गैरजिम्मेदाराना विपक्ष का रोल निभा रहे हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दें। सोमवार को मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नड्डा ने भारत की विदेश नीति और ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता की टिप्पणियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के उद्देश्य को समझना बहुत मुश्किल है।

जब वे सर्वदलीय बैठक में जाते हैं तो कहते हैं कि वे देश के साथ खड़े हैं, लेकिन जब वे बाहर निकलते हैं तो वे सवाल उठाने लगते हैं, ऐसे सवाल जो पूरी तरह से निराधार हैं। इसलिए वे एक गैर-जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नड्डा ने कहा कि जितना जनसंवाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करते हैं, उतना जयराम रमेश ने जीवन में बात नहीं की होगी। कांग्रेस के चुनाव आयोग पर उठाए गए सवाल पर नड्डा ने कहा कि जब वे कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जीतते हैं तो सब ठीक रहता है और हारते हैं तो सब खराब हो जाता है। कांग्रेस की तो यह आदत बन गई है। चार प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही विषय पर अलग-अलग आंकड़े लेकर आते हैं। कांग्रेस को अपने विषय में सोचना चाहिए। अपने नेतृत्व पर विचार करना चाहिए। नड्डा ने आर्थिक विकास, महिला सशक्तीकरण पहल और ऑपरेशन गंगा जैसे सफल प्रत्यावर्तन प्रयासों सहित प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर सरकार के 11 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार जनता के नेतृत्व वाली सरकार है। पिछले कुछ सालों में हमने पारदर्शिता लाई है और एक दूरदर्शी, भविष्योन्मुखी प्रशासन बनाया है। इसीलिए हम विकसित भारत की बात करते हैं। यह अमृत काल है। पिछले 11 सालों ने वास्तव में विकसित और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखी है। इस मौके पर नड्डा ने प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया।

देश की सर्वांगीण उन्नति के लिए दैनिक जीवन में लाना होगा राष्ट्रभक्ति का भाव : डॉ. मोहन भागवत

एजेंसी (हि.स.)

कानपुर

देश के विकास के लिए जरुरी है कि हम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें ताकि देश का पैसा देश के विकास में खर्च हो सके। साथ ही अपने दैनिक जीवन में राष्ट्रभक्ति का भाव लाना होगा। यही भाव हमें और हमारे देश को आगे ले जाएगा तभी देश की सर्वांगीण उन्नति सम्भव होगी। यह बातें तीन दिवसीय प्रवास पर कानपुर पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने सोमवार को प्रशिक्षण वर्ग के शिक्षार्थियों से वार्ता करते हुए कहीं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत अपने कानपुर प्रवास के अंतिम दिन सोमवार को वर्ग स्थल (दीनदयाल उपाध्याय इण्टर कॉलेज) की प्रातः शाखा पर रहे। इसके बाद वर्ग में शिक्षार्थियों के साथ वार्ता कर कार्यकताओं से उनके क्षेत्र में संघ को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि देश के उत्थान के

लिए दैनिक जीवन में राष्ट्र भाव लाना होगा। तभी हमारा देश और हम उन्नति कर सकेंगे।

प्रांत प्रचार प्रमुख डॉक्टर अनुपम ने बताया कि सरसंघचालक ने शिक्षार्थियों से वार्ता करते हुये उनके व्यक्तिगत जीवन पर भी चर्चा करते हुए पूछा कि यदि विद्यार्थी हैं तो कितनी देर अध्ययन करते हैं? व्यवसायी हैं तो व्यवसाय की कार्यावधि कितनी रहती है? उन्होंने कहा कि संघ का कार्यकर्ता जिस भी कार्य को करता है, एक साधक के रुप में करता है। जिस व्यवसाय को करें उस क्षेत्र का आदर्श व्यवसायी कहलायें। विद्यार्थी वही आदर्श विद्यार्थी होगा जो दूसरों के लिये प्रेरणा का केंद्र बने।

प्रधानमंत्री ने सभी से नमो ऐप पर भारत की विकास यात्रा पर सर्वेक्षण में भाग लेने का आग्रह किया

भारत ने पिछले 11 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से परिवर्तन देखा: नरेंद्र मोदी

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने पर कहा कि उनकी सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल में भारत न केवल सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है, बल्कि जलवायु कार्रवाई और डिजिटल नवाचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक प्रमुख वैश्विक आवाज भी बन गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर सेवा के 11 वर्ष हैशटैग के साथ कई पोस्ट किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की हर योजना के केंद्र में गरीब भाई-बहनों के साथ ही जन-जन का कल्याण सुनिश्चित करना रहा है। उज्ज्वला हो या पीएम आवास, आयुष्मान भारत हो या भारतीय जन औषधि या फिर पीएम किसान सम्मान निधि, इन सभी योजनाओं ने देशवासियों की उम्मीदों को नए पंख दिए हैं। हमने इस दौरान पूरी निष्ठा और सेवाभाव के साथ लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किया है।

प्रधानमंत्री ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि सुशासन और परिवर्तन पर स्पष्ट ध्यान दिया गया। 140 करोड़ भारतीयों के आशीर्वाद और सामूहिक भागीदारी से संचालित भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से परिवर्तन देखे हैं। ह्यसबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयासह्ण के सिद्धांत से प्रेरित होकर एनडीए सरकार ने गति, पैमाने और संवेदनशीलता के साथ पथप्रदर्शक परिवर्तन किए हैं। आर्थिक विकास से लेकर सामाजिक उत्थान तक, लोगों पर केंद्रित, समावेशी और सर्वांगीण प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आज भारत न केवल सबसे तेजी से

बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है, बल्कि जलवायु कार्रवाई और डिजिटल नवाचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक प्रमुख वैश्विक आवाज भी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपनी सामूहिक सफलता पर गर्व है, लेकिन साथ ही, हम एक विकसित भारत के निर्माण के लिए आशा, विश्वास और नए संकल्प के साथ आगे देखते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास से लेकर सामाजिक उत्थान तक सरकार ने जन-केंद्रित, समावेशी और सर्वांगीण प्रगति को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों को नमो ऐप के माध्यम से इस परिवर्तनकारी यात्रा का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि यह ऐप सरकार की उपलब्धियों को इंटरैक्टिव तरीके से प्रस्तुत करता है, जिसमें गेम, क्विज, सर्वेक्षण और अन्य प्रारूप शामिल हैं जो जानकारी देने के साथ ही लोगों को प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को सभी से नमो ऐप पर पिछले 11 वर्षों में भारत की विकास यात्रा पर सर्वेक्षण में भाग लेने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने सेवा के 11 वर्ष हैस टैग के साथ एक्स पोस्ट में कहा, ह्रआपके विचार सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। नमो ऐप पर इस सर्वेक्षण में भाग लें और हमें बताएं कि आप पिछले 11 वर्षों में भारत की विकास यात्रा को कैसे देखते हैं। प्रधानमंत्री ने नमो ऐप पर सर्वेक्षण का लिंक साझा किया है, जहां कोई भी व्यक्ति भारत की विकास यात्रा पर अपने विचार साझा कर सकता है। यह सर्वेक्षण पिछले 11 वर्षों में भारत की विकास यात्रा पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री ने जन मन सर्वेक्षण का भी उल्लेख किया है, जो भारत की विकास यात्रा पर केंद्रित है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से सरकार लोगों के विचारों और सुझावों को जानना चाहती है। उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार ने आज 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। दूसरी बार 30 मई 2019 को और तीसरी बार 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी।

भुभुजोत सुरंग सहित कई सड़क परियोजनाओं को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करे केंद्र सरकार : विक्रमादित्य सिंह

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्य की विभिन्न सड़क परियोजनाओं को लेकर केंद्र सरकार से महत्वपूर्ण आग्रह किए।

विक्रमादित्य सिंह ने खासतौर पर घटासनी-शिल्हा-बधानी-भुभुजोत-कुल्लू मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि यह मार्ग सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और भुभुजोत सुरंग के साथ इसे जोड़ने से न केवल कुल्लू क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि रक्षा सामग्री की आवाजाही भी सुचारु हो सकेगी। साथ ही यह मार्ग मौजूदा दूरी को 55 किलोमीटर तक कम करेगा, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। बैठक के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री ने एनएच-05 पर ढली से रामपुर तक फोरलेन सड़क निर्माण कार्य को प्राथमिकता पर लेने का भी अनुरोध किया। उन्होंने राज्य में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने की जरूरत पर भी बल दिया और कहा कि इनके शीघ्र पूर्ण होने से आम जनता को राहत मिलेगी।

राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत पांच राष्ट्रीय राजमार्गों को शामिल करने हेतु भेजे गए प्रस्ताव की जानकारी भी विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री को दी और उनके शीघ्र अनुमोदन की मांग की। इसके अतिरिक्त मंत्री ने केंद्रीय सड़क निधि के तहत लंबित 130 करोड़ रुपये की राशि को शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने राज्य के लिए सीआरएफ कार्यों की वार्षिक सीमा को 250 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की भी मांग रखी।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल सरकार की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने ढली से रामपुर तक फोरलेन परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी भी प्रदान की।

इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के सचिव अभिषेक जैन भी मंत्री के साथ उपस्थित रहे।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आठ न्यायाधीश परिवारों सहित घाटी के दौरे पर

एजेंसी (हि.स.)
श्रीनगर

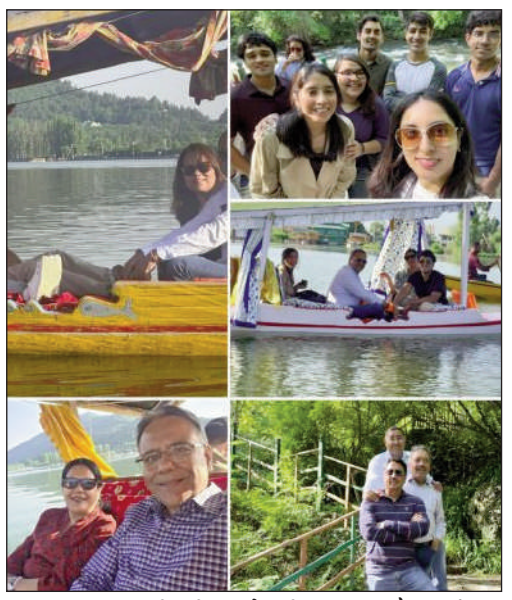

कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र का मनोबल बढ़ाने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आठ जस्टिस अपने-अपने परिवारों के साथ इस समय घाटी के दौरे पर हैं। उनकी यात्रा को क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और मजबूत विश्वास के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

घाटी के दौरे पर आने वाले गणमान्य व्यक्तियों में जस्टिस विनोद एस भारद्वाज, जस्टिस पंकज जैन, जस्टिस जसजीत सिंह बेदी, जस्टिस निधि गुप्ता, जस्टिस हरकेश मनुजा, जस्टिस अमन चौधरी, जस्टिस एन.एस. शेखावत और जस्टिस विक्रम अग्रवाल हैं। उनके कार्यक्रम में कश्मीर के प्रतिष्ठित आकर्षणों की यात्रा, शालीमार और निशात के राजसी मुगल गार्डन में टहलना, डल झील पर सूर्यास्त के समय शिकारा की सवारी, परी महल में ऐतिहासिक सैर और पोलो व्यू मार्केट की स्थानीय जीवंतता में डूबी शाम शामिल है। पहलगाम की घटना के तुरंत बाद इन जस्टिस की हाई प्रोफाइल यात्रा को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण आश्वासन के रूप में देखा जा रहा है। घाटी के होटल व्यवसायी, ट्रैवल एजेंट, शिल्पकार और स्थानीय गाइड पहले से ही बुकिंग और पूछताछ में वृद्धि की रिपोर्ट कर रहे हैं। श्रीनगर में एक टूर ऑपरेटर ने कहा कि उनकी उपस्थिति केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि यह देश के बाकी हिस्सों और उससे परे एक शक्तिशाली संदेश भेजती है कि कश्मीर सभी आगंतुकों के लिए स्वागत योग्य, शांतिपूर्ण और सुरक्षित है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस विक्रम अग्रवाल ने घाटी में सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने देश भर के पर्यटकों से कश्मीर आने और इसकी बेजोड़ प्राकृतिक सुंदरता और आतिथ्य का आनंद लेने का आग्रह किया।

इस यात्रा को स्थानीय पर्यटन अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत जरूरी मनोबल बढ़ाने वाला भी माना जा रहा है।

कई लोग इसे हाल की असफलताओं के बाद विश्वास बहाल करने में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देख रहे हैं। कश्मीर के मनमोहक परिदृश्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत यात्रियों को आकर्षित करते रहते हैं।

उपराज्यपाल ने दिव्यांगजनों के लिए सहायता और उपकरणों के बड़े पैमाने पर वितरण अभियान का किया उद्घाटन

एजेंसी (हि.स.)
श्रीनगर

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को दिव्यांगजनों के लिए सहायता और उपकरणों के बड़े पैमाने पर वितरण अभियान का उद्घाटन किया।

एक्स के मध्यम से उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए सहायता और उपकरणों के बड़े पैमाने पर वितरण अभियान का आज उद्घाटन किया गया। दो प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजनाओं आरवीवाई और एडीआईपी के तहत जम्मू के समाज कल्याण निदेशालय द्वारा की गई पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर बनाना और दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना है।

इस बीच उपराज्यपाल ने कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि दिव्यांग लोगों में विशेष क्षमताएँ होती हैं और उनके पास अद्वितीय शक्तियाँ और दृष्टिकोण होते हैं। मैं उनके असाधारण लचीलेपन, समस्या-समाधान कौशल और समाज में दूसरों के प्रति सहानुभूति की प्रशंसा करता हूँ। मैं अपने दिव्यांगजनों को आश्वस्त करता हूँ कि प्रशासन जीवन के हर क्षेत्र में उनके लिए समानता और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और अधिकारों, पहुँच और सम्मान के मामले में उनके साथ हमेशा समान व्यवहार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन भी हमारे वरिष्ठ नागरिकों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुरूप निष्पक्षता और अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करूंगा कि प्रणालीगत असमानताएं और पहुंच संबंधी बाधाएं- भौतिक, डिजिटल और सामाजिक- पूरी तरह से दूर हो जाएं।

मोदी सरकार के 11 वर्षः सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का स्वर्णिम कालखंड : डॉ. राजीव बिंदल

एजेंसी (हि.स.)
मंडी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने रविवार को सुंदरनगर में आयोजित संगठनात्मक जिला कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने इन 11 वर्षों को भारत के पुनरुत्थान का कालखंड बताया।

डॉ. बिंदल ने कहा कि वर्ष 2014 भारतीय इतिहास में एक टर्निंग प्वाइंट बनकर सामने आया, जब देश को भ्रष्टाचार और घोटालों से त्रस्त राजनीतिक परिदृश्य से उबार कर एक निर्णायक नेतृत्व मिला। उन्होंने कांग्रेस के 2004 से 2014 तक के कार्यकाल को घोटालों का दशक बताते हुए कोयला, 2जी, 3जी, कॉमनवेल्थ, हेलिकॉप्टर और भूमि घोटालों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उस समय भारत की अंतरराष्ट्रीय साख को गहरा धक्का लगा और अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर पहुंच गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए डॉ. बिंदल ने कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में चौथे स्थान पर है। जिस देश को कभी फ्रैजाइल इकोनॉमी कहा जाता था, वह अब एक मजबूत विकास मॉडल बन चुका है।

उन्होंने केंद्र सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि फोरलेन और नेशनल हाईवे का विस्तार, 5जी नेटवर्क, एयरपोर्ट्स का विकास, एक लाख से अधिक मेडिकल सीटों का सृजन, 8 नए एम्स, 7 आईआईएम और कई आईआईटी, ट्रिपल आईटी संस्थान स्थापित कर शिक्षा और स्वास्थ्य में क्रांति लाई गई है।

डॉ. बिंदल ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए कदमों को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि भारत अब हथियारों का निर्यातक बन गया है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयरस्ट्राइक का उल्लेख करते हुए कहा कि इन कार्रवाइयों ने भारत की सामरिक शक्ति को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया।

एलजी मनोज सिन्हा ने माता वैष्णो देवी तीर्थस्थल के लिए सीसीटीवी निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया

एजेंसी (हि.स.)
कटरा

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को श्री माता वैष्णो देवी तीर्थस्थल के लिए एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र के साथ सीसीटीवी निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल ने कहा कि अत्याधुनिक तकनीक श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए वास्तविक समय की निगरानी और भीड़ प्रबंधन को सक्षम करेगी और यह परेशानी मुक्त तीर्थयात्रा सुनिश्चित करेगी।

परियोजना के तहत कटरा में स्थित एक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र और स्थानीय निगरानी और समन्वय के लिए तीर्थयात्रा मार्ग पर 7 उप-नियंत्रण केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो सभी संवेदनशील और उच्च-यातायात क्षेत्रों की हफ्ते के सातों दिन व 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करेंगे। पूरे तीर्थ क्षेत्र में 700 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें 170 नए हाई-डेफिनिशन आईपी कैमरे और 500 से अधिक मौजूदा कैमरों का एकीकरण है जो प्रवेश और निकास बिंदुओं, सभी क्षेत्रों और तीर्थयात्रा मार्ग सहित सभी महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थानों को कवर करते हैं।

इस परियोजना में एआई-आधारित एनालिटिक्स और उन्नत प्रौद्योगिकी तंत्र जैसे हावभाव पहचान, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर), चेहरे की पहचान, घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली, भीड़ प्रबंधन उपकरण भी शामिल हैं। एसएमवीडीएसबी के सीईओ अंशुल गर्ग ने एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की तकनीकी विशेषताओं और मंदिर के दैनिक कामकाज में इसके प्रत्याशित लाभों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।

उपराज्यपाल ने केंद्र में इंजीनियरों और परिचालन कर्मचारियों के साथ भी बातचीत की। उन्होंने केंद्र की उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण और सुरक्षा एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ निर्बाध सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया।

इस अवसर डॉ. अशोक भान, सदस्य, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, श्री भीम सेन टूटी आईजीपी जम्मू, सुश्री निधि मलिक डिप्टी कमिश्नर रियासी और पुलिस, सुरक्षा एजेंसियों और श्राइन बोर्ड के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

स्पेशल एजुकेटर टेट परीक्षा 11 जून को, एडमिट कार्ड वेबसाइट पर

एजेंसी (हि.स.)
धर्मशाला

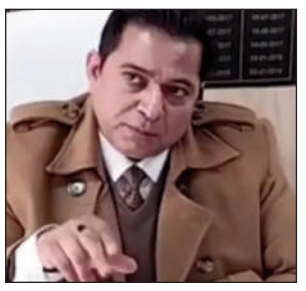

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही टेट परीक्षाओं की कड़ी में 11 जून को स्पेशल एजुकेटर प्री प्राइमरी से लेकर पांचवी कक्षा तक के टेट की परीक्षा सुबह के सत्र में आयोजित की जाएगी। इसी तरह 11 जून को ही दोपहर बाद स्पेशल एजुकेटर छठी कक्षा से लेकर जमा दो तक के टेट विषय की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि दोनों परीक्षाओं के लिए कुल सात परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिनमें सुबह के सत्र में आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए चार जबकि दोपहर बाद आयोजित होने वाली दूसरी परीक्षा के लिए तीन परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुबह के सत्र में आयोजित होने वाली परीक्षा 10:00 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी जबकि दोपहर बाद 2:00 बजे से लेकर 4:30 बजे तक परीक्षा का आयोजन होगा।

उन्होंने बताया कि स्पेशल एजुकेटर प्री प्राइमरी टेट के लिए 1035 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है जबकि स्पेशल एजुकेटर छठी से लेकर जम दो तक के टेट विषय के लिए 447 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। उन्होंने बताया कि इन परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं बोर्ड की वेबसाइट में जाकर अभ्यर्थी अपनी डेट ऑफ बर्थ या एप्लीकेशन नम्बर डालकर एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं।

कश्मीर ने छह अतिरिक्त पारंपरिक शिल्पों के लिए जीआई पंजीकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया की शुरू

श्रीनगर। स्थानीय कारीगरों की अनूठी शिल्पकला की रक्षा के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए, हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग कश्मीर ने छह अतिरिक्त पारंपरिक शिल्पों के लिए भौगोलिक संकेत (जीआई) पंजीकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य कम-ज्ञात कला रूपों को पुनर्जीवित करना और विशिष्ट वैश्विक बाजारों में उनकी भागीदारी को बढ़ाना है। जीआई टैगिंग के लिए पहचाने गए शिल्पों में कॉपरवेयर (स्थानीय रूप से कंदकारी के रूप में जाना जाता है) चांदी के बर्तन, हाउसबोट शिल्प कौशल, टेपेस्ट्री, कश्मीर तिला कढ़ाई और आरी स्टेपल कढ़ाई शामिल हैं। विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि हमने छह और शिल्पों के लिए चेन्नई में जीआई रजिस्ट्री को औचित्य और डोजियर जमा कर दिए हैं। टैगिंग प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। यह प्रक्रिया कठोर है इसमें विस्तृत जांच शामिल है और इसमें काफी समय लगता है। तांबे के बर्तन एक पारंपरिक कश्मीरी शिल्प है जिसमें तांबे से बने जटिल रूप से डिजाइन किए गए बर्तन और सजावटी सामान बनाना शामिल है। चांदी के बर्तन एक परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण शिल्प है जिसमें चांदी से बने जटिल रूप से डिजाइन किए गए सजावटी और उपयोगी सामान बनाना शामिल है। टेपेस्ट्री कश्मीर में प्रचलित एक पारंपरिक शिल्प है जिसमें ऊनी धागों का उपयोग करके सूती कपड़े पर जटिल डिजाइनों को हाथ से बुनना शामिल है। जीआई पंजीकरण जालसाजी के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है अनधिकृत उपयोग को रोकता है और उत्पादों की उत्पत्ति को प्रमाणित करके निर्यात को बढ़ावा देता है। अधिकारी ने कहा कि यह भी सुनिश्चित होता है कि आर्थिक लाभ वास्तविक स्थानीय कारीगरों तक पहुंचे। जम्मू और कश्मीर में जीआई-पंजीकृत हस्तशिल्प की कुल संख्या 18 है। इससे पहले इस साल मार्च में आठ शिल्प कश्मीर नमदा, कश्मीर गब्बा, कश्मीर विलो बैट, कश्मीर ट्वीड, क्रूवेल, चेन स्टिच, शिकारा और वाग्गुव को जीआई का दर्जा दिया गया था। इससे पहले प्रसिद्ध कश्मीरी सोजनी, पश्मीना, कानी शॉल, पेपर माचे, खतमबंद और अखरोट की लकड़ी की नक्काशी को पहले ही जीआई प्रमाणन मिल चुका है।

मौसम

सांबा में सबसे अधिक 44 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज

जम्मू संभाग के कई हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी

एजेंसी (हि.स.)
जम्मू

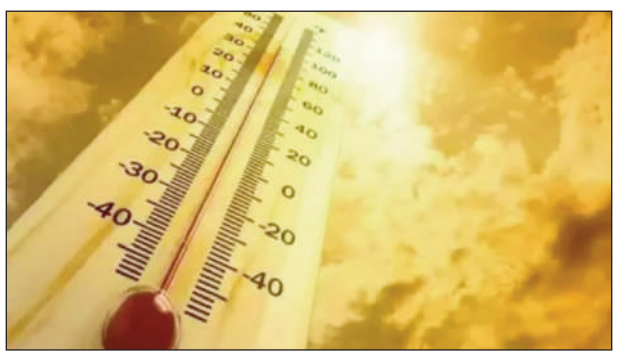

पिछले कुछ दिनों से जम्मू संभाग के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है जबकि रविवार को सांबा में सबसे अधिक 44 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

मौसम विज्ञानियों ने अगले पांच दिनों के दौरान जम्मू क्षेत्र में भीषण गर्मी की स्थिति की भविष्यवाणी की है जिसमें सोमवार शाम को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। जम्मू क्षेत्र के कुछ हिस्सों में 9 जून की शाम को आंधी और गरज के साथ बारिश होने की भविष्यवाणी की गई है।

एसकेयूएएसटी-जम्मू के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के मुख्य वैज्ञानिक डॉ महेंद्र सिंह ने कहा कि अगले 5-6 दिनों के दौरान क्षेत्र में तापमान में और वृद्धि होगी। हालांकि, सोमवार शाम को आंधी और उसके बाद क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की उम्मीद है। सिंह ने कहा कि इन गर्म दिनों में पराबैंगनी किरणों की बढ़ती तीव्रता लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रही है। आम जनता को पीक आवर्स के दौरान खास तौर पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच सीधी धूप में जाने से बचना चाहिए। बच्चों और बुजुर्गों को दोपहर के समय अल्ट्रा-वायलेट किरणों के प्रभाव से बचाना चाहिए और सभी लोगों को इन दिनों में अधिक मात्रा में तरल पदार्थ लेने की सलाह दी जाती है। एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए एसकेयूएएसटी के मुख्य वैज्ञानिक ने कहा कि इस वर्ष मानसून एक सप्ताह आगे है। जून के तीसरे सप्ताह के दौरान मानसून के जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करने की उम्मीद है। 20-21 जून को जम्मू क्षेत्र में प्री-मानसून वर्षा होने की उम्मीद है। इस बीच एक मौसम अधिकारी ने कहा कि अगले पांच दिनों के दौरान मौसम लगभग शुष्क और गर्म रहेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू में रविवार को अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम के दौरान अब तक का सबसे अधिक है। सांबा में अधिकतम तापमान 44 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। यह जम्मू संभाग में सबसे अधिक था। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में जम्मू, सांबा और कठुआ का तापमान और बढ़ सकता है। रविवार को कटरा के पवित्र कस्बे में अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस, भद्रवाह में 31.8, बनिहाल कस्बे में 32.5 जबकि बटोत में अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजौरी में दिन का तापमान 35.9 डिग्री सेल्सियस, पुंछ में 35.4, किश्तवाड़ में 30.9 जबकि रियासी कस्बे में 38.5 डिग्री सेल्सियस रहा। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो दिन के लिए सामान्य से करीब 4 डिग्री अधिक था। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में दिन का तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम में 27.8 और कोकरनाग कस्बे में 30.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

संक्षिप्त-समाचार

ढाबा संचालक से चरस बरामद, गिरफ्तार

शिमला। शिमला जिला की ननखड़ी तहसील में पुलिस ने गश्त के दौरान एक ढाबा संचालक के पास से चरस बरामद किया है। आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले के अनुसार रविवार की शाम पुलिस थाना ननखड़ी की टीम ननखड़ी चौक पर नियमित गश्त कर रही थी, तो उन्हें गुप्त सूचना मिली कि ननखड़ी का बड़ोग निवासी बाबूराम पुत्र जियालाल अपने ढाबे में चरस बेचने का अवैध कारोबार करता है। सूचना के आधार पर तुरंत बाबूराम के ढाबे पर दबिश दी गई। तलाशी के दौरान ढाबे से 158.90 ग्राम चरस बरामद की गई। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि बरामद चरस को कब्जे में लेकर एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी कानूनी कार्रवाई जारी है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी चरस की सप्लाई कहां से लाता था और इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं है।

सैंज खड्ड में डूबने से किसान की मौत

शिमला। शिमला जिला के नेरवा क्षेत्र में खड्ड (उपनदी) में डूबने से 38 वर्षीय किसान की जान चली गई। रविवार शाम यह घटना उस समय घटी जब किसान सैंज खड्ड को पार कर रहा था। अचानक पैर फिसलने से वह खड्ड में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान निक्का राम पुत्र स्वर्गीय रामसा राम निवासी गांव गवाये डाकघर धारचांदना तहसील कुपवी जिला शिमला के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही थाना नेरवा से एएसआई हरदीप चौहान अपनी टीम के साथ सीएच नेरवा पहुंचे, जहां मृतक को स्थानीय लोगों और परिजनों द्वारा लाया गया था। प्राथमिक जांच में पाया गया कि निक्का राम खेतों से लौटते समय खड्ड पार कर रहा था। इसी दौरान फिसलकर पानी में गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला दुर्घटनावश डूबने का है और इसमें किसी भी प्रकार की आपराधिक या संदिग्ध गतिविधि सामने नहीं आई है। शव को सीएच नेरवा में रखा गया है जहां आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस ने बीएनएसएस की धारा 194 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि बीते 24 घण्टों में शिमला जिला में डूबने से ये तीसरी मौत है। इससे पहले कोटखाई इलाके में मां व बेटी की गिरी नदी में डूबने से मौत हुई है।

केंद्र से नहीं मिली अतिरिक्त मदद : हर्षवर्धन चौहान

शिमला। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार वित्तीय संकट के बावजूद राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश को अब तक एक भी पैसे की अतिरिक्त आर्थिक मदद नहीं मिली है, इसके बावजूद सरकार जनता की जरूरतों को प्राथमिकता दे रही है। मंत्री चौहान ने भाजपा नेताओं विशेषकर सांसदों पर हमला करते हुए कहा कि वे बार-बार प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र की जिन योजनाओं का उल्लेख भाजपा सांसद करते हैं, वे केवल हिमाचल के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए समान रूप से लागू होती हैं। ऐसे में इसे हिमाचल को दी गई विशेष मदद बताना सरासर झूठ है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा राज्य सरकार को ह्यशुल्क की सरकारह्ण कहे जाने पर भी मंत्री चौहान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में पर्ची शुल्क वसूलने का निर्णय रोगी कल्याण समितियों का होता है, न कि सरकार का। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर को तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने और जनता को भ्रमित करने की आदत हो चुकी है। उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार को राज्य की वर्तमान आर्थिक बदहाली का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार को सत्ता ऐसे समय में मिली जब खजाना खाली था, बावजूद इसके मौजूदा सरकार योजनाओं को न केवल जारी रखे हुए है, बल्कि नई पहलें भी कर रही है। वहीं, उद्योगों के पलायन के भाजपा के दावों को सिरे से खारिज करते हुए हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य से किसी भी उद्योग का स्थानांतरण नहीं हुआ है। जो इकाइयाँ बंद हुई हैं, उनके पीछे उनके निजी कारण या आर्थिक कमजोरी रही है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने और नए उद्योगों को आकर्षित करने के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही है।

नशे के खिलाफ शिमला में चलेगा 15 दिवसीय जागरूकता अभियान, विजेताओं को मिलेंगे पुरस्कार

शिमला। जिला शिमला में 26 जून को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में गेयटी थियेटर में एक विशेष जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह निर्णय उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित एक बैठक में लिया गया। उपायुक्त ने बताया कि आगामी 15 दिनों तक जिलेभर में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत शिक्षण संस्थानों में नारा लेखन, भाषण, कविता लेखन, चित्रकला प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं और मैराथन जैसी गतिविधियाँ आयोजित होंगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला के सामाजिक कार्य विभाग के सहयोग से एक विशेष सेमिनार आयोजित किया जाएगा। साथ ही, हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, धंडल में भी कार्यशाला का आयोजन होगा। जिला भर में स्वास्थ्य विभाग की चिकित्सकीय टीम काउंसलिंग शिविर लगाएगी और फील्ड में तैनात कर्मचारी भी लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेंगे। उपायुक्त ने कहा कि ह्यनशा मुक्त भारत अभियानह्ण के अंतर्गत भी विशेष गतिविधियाँ की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में शिमला के ग्रीष्मोत्सव में आयोजित टेबल टेनिस प्रतियोगिता को भी नशे के विरुद्ध संदेश देने के लिए जोड़ा गया था। जिला पुलिस द्वारा बीते वर्ष में नशा तस्करी के कई बड़े मामलों का भंडाफोड़ किया गया है, लेकिन अब आमजन को भी इस दिशा में आगे आना होगा।

दैनिक सिटी दर्पण आईना सच का

नवोन्मेषकः स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा
संस्थापकः सतपॉल शर्मा

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक भुपेंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्स प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1 सेक्टर-40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित- 160036

सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।

स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।
संपर्कः 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

बाढ़ और जलभराव से निपटने के लिए अलर्ट मोड में रहें अधिकारी: श्रुति चौधरी

मानसून सीजन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन

संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने आगामी मानसून सीजन के दौरान संभावित जलभराव और बाढ़ की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ फील्ड में सक्रिय रहकर आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य के किसी भी क्षेत्र में पीने के पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए और इसके लिए पानी की आपूर्ति व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ नियत्रंण से संबंधित आवंटित कार्यों की सभी परियोजनाओं को समय रहते पूरा किया जाए, ताकि प्रदेश में मानसून के दौरान कोई जलभराव की स्थिति उत्पन्न ना हो।

सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने सोमवार को चंडीगढ़ में मानसून के दौरान संभावित जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए और प्रदेश में पानी की व्यवस्था को लेकर सिंचाई विभाग व पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सिंचाई मंत्री को अवगत कराया गया कि प्रदेश में कुल 873 ड्रेन में से 676 साफ किया जाना है, जिसमें से 470 ड्रेन साफ की जा चुकी हैं, शेष ड्रेन की सफाई 20 जून तक करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बाढ़ नियंत्रण के लिए अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक परियोजनाओं परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी जिनमें से 194 का कार्य प्रगति पर है जिनमें से 8 कार्य पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी कुशलता से काम करें और सुनिश्चित करें कि ये परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी हों, अन्यथा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री मोहम्मद शाईन ने मंत्री को अवगत करवाया कि ऐसे जिले जहां बारिश से जलभराव की आशंका अधिक रहती है वहां पानी की निकासी के लिए विभिन्न प्रकार के पंप, मोटर, पैनल आदि की खरीद और पाइपलाइन बिछाने, के संबंध में सभी जिलाधिकारियों से जिलावार रिपोर्ट भी ली।

बैठक में मंत्री को इस बात से भी अवगत कराया कि 56वीं हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में 209 लघु अवधि की ड्रेन की सफाई व सीवरेज की सफाई का कार्य भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। बैठक में हरियाणा जल संसाधन एवं प्राधिकरण की चेयरपर्सन श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा व विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

आईएएस, आईपीएस व एचसीएस अधिकारी विद्यार्थियों को परीक्षाओं में पारंगत बनाने में देंगे योगदान: महीपाल ढांडा

संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों कां ढांचागत विकास कराने के साथ-साथ विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दिलाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का राजकीय स्कूलों का 10वीं व 12वीं कक्षा के बेहतरीन परीक्षा परिणाम रहे हैं। राजकीय स्कूलों के विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास व उन्हें प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करने की योजना बनाई गई है। हर जिले के आईएएस, आईपीएस व एचसीएच अधिकारी महीने में चार दिन चार सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को शिक्षा व प्रतियोगिता परीक्षाओं में पारंगत बनाने के लिए योगदान देंगे। विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियमों की भी जानकारी दी जाएगी। इस बारे में अधिकारियों को पत्र लिखकर सहयोग की अपील की है। शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा आज अपने चंडीगढ़ निवास पर पत्रकारवार्ता कर रहे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश में सबसे पहले हरियाणा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। इस नीति के अनुरूप पाठयक्रम तैयार किए जा रहे हैं। भविष्य में इसके सार्थक परिणाम सामने आएंगे।

उन्होंने कहा कि सुपर 100 कार्यक्रम गरीब विद्यार्थियों के लिए आशा की नई किरण लेकर आया है। इस बार आईआईटी व जेईई एडवांस 2025 परीक्षा में सुपर 100 के सरकारी स्कूलों के 72 विद्यार्थियों ने क्वालीफाई किया है। सकारात्मक पहलू यह है कि परीक्षा में 24 बेटियों ने सफलता हासिल की है। यह प्रदेश सरकार की लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन सुविधा देने का नतीजा है। एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने कहा कि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 10 से 12वीं कक्षा तक का सेलेब्स इसके अनुरूप तैयार किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी करने उपरांत अपने कैरियर का चयन कर सकें। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने पहल की है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय स्कूलों की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में ग्राम पंचायतों का सहयोग लिया जाएगा। इस बारे में पंचायतों को पत्र लिखकर अवगत भी करा दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रीष्म कालीन छुट्टियों में शिक्षक घर-घर जाकर राजकीय स्कूलों में विद्यार्थियों को संख्या बढ़ाने में जुटे हैं। इसमें ग्राम पंचायतों का भी सहयोग लिया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि शिक्षा निदेशालय में उसके नाम से किसी भी व्यक्ति का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वह नजदीक का रिश्तेदार ही क्यों न हो।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री ने ली अधिकारियों की बैठक

संवाददाता
चंडीगढ़

आदमपुर के निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के दिए निर्देश

हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण (भवन व सडकें) मंत्री श्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा है कि इस साल के अंत तक आदमपुर में अमृत योजना के तहत चल रहे कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। यहां शहरी तर्ज पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। रणबीर सिंह गंगवा जिला हिसार में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण (भवन व सडकें) विभागों के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने सीवरेज और पेयजल संबंधी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग तथा मार्केटिंग कमेटी के कार्य शुरू हो चुके हैं। एचएसवीपी के तहत होने वाले कार्यों का टेंडर हो गया है। विकास कार्यों के मद्देनजर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं कि पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्राथमिकता आधार पर पूरा किया जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक में आदमपुर क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए ताकि आमजन को समय पर सुविधाएं मिल सकें। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार विकास कार्यों को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और कोई भी लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने अधूरी परियोजनाओं की सूची लेकर संबंधित अधिकारियों से उनका स्टेटस जाना और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

हरित हरियाणा के लिए एक पेड़ माँ के नाम 2.0

संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाने और मजबूत सार्वजनिक भागीदारी से पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने के मकसद से ह्यएक पेड़ माँ के नाम 2.0ह्ल के नाम से एक महत्वाकांक्षी पहल की है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आज यहां एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्य कार्य योजना की समीक्षा की गई। बैठक में इस अभियान को प्रमुख राष्ट्रीय मिशनों के साथ जोड़ने और जिला स्तर पर प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने की रणनीति बनाई गई।

बैठक के दौरान, मुख्य सचिव श्री रस्तोगी ने जोर देकर कहा कि ह्यएक पेड़ माँ के नाम 2.0ह्ल को संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान को मनरेगा, जल शक्ति अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन और राष्ट्रीय हरित राजमार्ग मिशन जैसी प्रमुख राष्ट्रीय योजनाओं के साथ जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कदम से सामूहिक प्रयासों से पारिस्थितिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।

साथ ही, योजना का प्रभाव और पहुंच भी बढ़ेगी। उन्होंने पिछले वर्ष लगाए गए पौधों की गहन समीक्षा करने की आवश्यकता जताई, ताकि उनका सतत रखरखाव और विकास सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।

वर्ष 2025-26 के दौरान चलाए जाने वाले इस अभियान में बड़े पैमाने पर पौधारोपण गतिविधियों पर जोर दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के तहत इको क्लब फॉर मिशनलाइफ के माध्यम से स्कूल आधारित पहलों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि इस अभियान में अधिक से अधिक युवाओं और छात्रों को शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि कम उम्र में पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देने से दूरगामी सामाजिक लाभ होंगे।

संक्षिप्त-समाचार

राज्यपाल ने बाबा बंदा सिंह बहादुर और भगवान बिरसा मुंडा को उनके शहीदी दिवस पर दी श्रद्धांजलि

चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज भारतीय इतिहास के दो महान नायकों, बाबा बंदा सिंह बहादुर और भगवान बिरसा मुंडा को उनके शहीदी दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उत्पीड़न के खिलाफ उनके साहसी संघर्ष और सामाजिक न्याय के लिए उनके अमर बलिदान को याद किया। राज्यपाल ने कहा कि आज हम बाबा बंदा सिंह बहादुर के अद्वितीय साहस और बलिदान का सम्मान करते हैं, जिन्होंने पंजाब में न्याय और स्वशासन की नींव रखी और मुगलों के अत्याचार के खिलाफ डटे रहे। धर्म के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनका सर्वोच्च बलिदान पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री दत्तात्रेय ने भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को भी स्मरण किया, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आदिवासी समुदायों का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा का निर्भीक संघर्ष और समतापूर्ण समाज का उनका स्वप्न भारत की सांस्कृतिक धरोहर और आदिवासी गौरव का प्रतीक है। उनकी विरासत हमें सामाजिक सशक्तिकरण और एकता का पाठ पढ़ाती है। राज्यपाल ने देश के युवाओं से इन महानायकों के जीवन से प्रेरणा लेकर एक सशक्त, समावेशी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आान किया। उन्होंने नागरिकों से बाबा बंदा सिंह बहादुर और भगवान बिरसा मुंडा के मूल्यों - साहस, बलिदान, सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता की भावना को जीवित रखने की अपील की। राज्यपाल ने सभी से इन शहीदों के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने का अनुरोध किया, ताकि एक समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो सके।

श्रीमती कृष्णा गोयल फाउंडेशन व भाविप ने अंबेडकर चौक पर लगाया वाटर कूलर

लाडवा। भारत विकास परिषद लाडवा एवं श्रीमती कृष्णा गोयल फाउंडेशन लाडवा द्वारा भीषण गर्मी के मद्देनजर शहर के मुख्य चौराहे अंबेडकर चौक पर वाटर कूलर लगाया गया। सचिव संजीव मंगला ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर की मुख्य समाजसेवी श्रीमती कृष्णा गोयल के जन्मदिन के अवसर पर श्रीमती कृष्णा गोयल के कर कमलों द्वारा मुख्य चौराहा अंबेडकर चौक पर वाटर कूलर का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि इस चौराहे से प्रतिदिन हजारों लोग यात्रा पर निकलते है। इस भीषण गर्मी में उन्हें शीतल जल प्रदान करने के उद्देश्य से यह वाटर कूलर लगवाया गया है ताकि राहगीर इसका भरपूर लाभ उठा सके। श्रीमती कृष्णा गोयल फाउंडेशन के संस्थापक अमित गोयल ने इस अवसर पर भारत विकास परिषद का धन्यवाद किया तथा कहा कि हम जरूरतमंद की मदद के लिए हर समय तैयार हैं। इस अवसर पर विजेंदर गोयल, सुनील गोयल, बिट्टू कंसल, अंजू सिंहल, शोभा गोयल, प्रियंका गोयल, संगीता गर्ग, प्रियंका गोयल एवं भारत विकास परिषद के सभी सदस्य उपस्थित थे।

मृदा एवं जल परीक्षण से किसानों को भूमि के पोषक तत्वों की मात्रा की मिलती है पूर्ण जानकारी

संवाददाता
लाडवा

वरिष्ठ समन्वयक डॉ. बलजीत सिंह सहारण ने कहा कि मृदा एवं जल परीक्षण के बाद कृषि करने से किसानों को बहुत अधिक लाभ हो रहा है। मृदा परीक्षण से किसानों को अपनी भूमि के अंदर के सभी पोषक तत्वों की मात्रा की जानकारी होने के बाद उन्हें पूरा करना आसान है। जो कम खर्च पर फसल का उत्पादन बढ़ाने में सहयोगी बन रही है। डॉ. सहारण ने बताया कि किसानों का बढ़ता सहयोग और उत्साह इस अभियान की सफलता का प्रमाण है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तत्वावधान में 29 मई से विकसित भारत संकल्प अभियान-2025 चलाया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) कुरुक्षेत्र की दो टीमों ने बाबैन खंड के छह गांव भगवानपुर, मचेरी, कसीथल, धनानी, इशरहेड़ी और बीर कलवा में जागरूकता अभियान चलाया। वरिष्ठ समन्वयक डॉ. बलजीत सिंह सहारण के मार्गदर्शन में चल रहे इस अभियान में किसानों को धान की सीधी बिजाई, मृदा एवं जल परीक्षण, मशरूम उत्पादन, पोषण वाटिका की स्थापना, मौसम आधारित कृषि जानकारी आदि विषयों पर प्रशिक्षित किया गया। केवीके की दो टीमों का नेतृत्व फसल वैज्ञानिक डॉ. सरिता और मृदा विज्ञान विशेषज्ञ डॉ. कविता ने किया। अन्य विशेषज्ञों में वानिकी वैज्ञानिक डॉ. एमके सिंह, पादप रोग विज्ञानी डॉ. फतेह सिंह, गृह विज्ञान विशेषज्ञ डॉ. ललिता और मौसम विज्ञानी डॉ. ममता भी किसानों के मार्गदर्शन में सक्रिय हैं। अभियान में किसानों को भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल के वैज्ञानिकों ने जौ की उपयोगिता और बीज पंजीकरण पोर्टल की जानकारी दी। एनडीआरआई के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम गभार्धान के लाभ बताए। पशु चिकित्सकीय टीम ने पशु क्रेडिट कार्ड योजना और बागवानी विभाग के अधिकारियों ने सब्सिडी योजनाओं की जानकारी दी। किसानों ने मिट्टी परीक्षण, जल संरक्षण और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों पर गहन चर्चा की और वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त किया।

लाडवा में पांच दिवसीय अध्यापक प्रशिक्षण कार्यशाला सम्पन्न

संवाददाता
लाडवा

खंड शिक्षा अधिकारी नीलम सैनी के निर्देशन एवं बीआरपी कोमल देशवाल के नेतृत्व में पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लाडवा में आयोजित पाँच दिवसीय कार्यशाला सोमवार को सम्पन्न हुई। कार्यशाला का आयोजन नई शिक्षा नीति 2020 के तहत निपुण हरियाणा मिशन के अंतर्गत किया गया। कार्यशाला में अध्यापकों ने कक्षा पहली से तीसरी के लिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए गुर सीखे। इस कार्यक्रम में तीन बैच में कुल 125 शिक्षकों ने प्रशिक्षण लिया।

खण्ड शिक्षा अधिकारी नीलम सैनी ने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य शिक्षण क्षेत्र में नवाचार और नए कौशलों का विकास करना है। इससे शिक्षकों की शैक्षिक गुणवत्ता में निखार आएगा और बच्चों में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या कौशल को बढाने में मदद मिलेगी। इसका उद्देशय केवल बच्चों को शिक्षित करना है बल्कि उनको शिक्षा के माध्यम से अच्छे संस्कार भी देना है। ताकि वे आगे चलकर सुदृढ़ और सुसंस्कृत समाज का निर्माण कर सके। यह कार्यक्रम निपुण भारत मिशन कार्यक्रम को सफल बनाने में मील का पत्थर साबित होगें।

उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण हेतु खण्ड लाडवा में कार्यरत प्राथमिक अध्यापकों के कुल पांच बैच बनाए गए हैं, पहले चरण में तीन बैच का प्रशिक्षण पांच से नौ जून के बीच आयोजित किया जबकि शेष दो बैचों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 10 जून को शुरू होगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में एबीआरसी गुरुचरण कौर, की रिसोर्स पर्सन (केआरपी) रीता जांगड़ा, सुषमा, ऋतु धीमान, कुसुम, प्रियंका, हेमा व अमन ने अहम भूमिका निभाई तथा अध्यापकों को विभाग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार बारीकी से प्रशिक्षण दिया।

हरियाणा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी लोकायुक्त की कार्यवाही

संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा में लोकायुक्त अब अपनी कार्यवाही के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सुविधा अपनाएंगे। ये निर्देश राज्य सरकार की उस व्यापक पहल का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य नए केंद्रीय आपराधिक कानूनों और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी तरह की आधिकारिक सम्पर्क या पारस्परिक व्यवहार के लिए ऑडियो-विजुअल इलेक्ट्रॉनिक साधनों का लाभ उठाना है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों व निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, उप-मंडल अधिकारियों और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें इन नए निदेशों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं को एकीकृत करने का यह निर्णय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अनुरूप है। विशेष रूप से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 336 के तहत कुछ मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 530 के तहत जांच और कार्यवाही के लिए स्पष्ट रूप से ऑडियो-विजुअल इलेक्ट्रॉनिक साधनों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ह्यउत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम सर्वोच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का संघ और अन्य शीर्षक से सिविल अपील संख्या 23-24 ऑफ 2024 में, एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है। इसमें भी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति को बढ़ावा दिया गया है। इन घटनाक्रमों की प्रतिक्रिया में, राज्य सरकार ने प्रशासनिक न्याय विभाग द्वारा 31 जनवरी, 2025 जारी एक अधिसूचना के माध्यम से, आधिकारिक रूप से नामित कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं की स्थापना को अधिसूचित किया है।

उत्पादन

बागवानी क्षेत्र को लाभदायक बनाने के लिए कई गतिविधियां

नई बागवानी तकनीक, बेहतर फल उत्पादन - किसानों के लिए बदलाव की किरण

अनिल गोयल
लाडवा,

हरियाणा प्रदेश सरकार की पहल पर बागवानी विभाग हरियाणा द्वारा इजराइल के कृषि विशेषज्ञों के साथ मिलकर उन्नत बागवानी तकनीक को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देशय से अप्रैल 2016 के दौरान जिला कुरुक्षेत्र के लाडवा ब्लॉक में उप उष्ण कटिबंधीय फल केन्द्र की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इस केंद्र की बागडोर उपनिदेशक उद्यान डॉ राकेश कुमार के हाथों में है। डॉ राकेश कुमार से विशेष बातचीत के दौरान उनके द्वारा इस परियोजना के मूलभूत उद्देश्यों से अवगत कराया गया।

उन्होंने बताया कि इस केन्द्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य किसानों को पारम्परिक खेती के स्थान पर बागवानी फसलों के प्रति जागरूक करके उनकी आय में वृद्धि करना है। केंद्र पर किसानों को प्रदर्शन के माध्यम से प्रेरित करने एवं उन्नत तकनीक बारे प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से आम, नाशपाती, आड़ू, आलु, बुखारा, चीकू, लीची, अमरूद, सेब, अनार, एवं जामुन इत्यादि फलों की कई किस्मों के प्रदर्शन स्थल स्थापित किए गए हैं।

स्थापना के समय से ही यह केन्द्र अपनी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से निरन्तर किसानों के कल्याण के लिए प्रयासरत है। किसानों को केन्द्र के माध्यम से बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने व लाभदायक बनाने के लिए निम्नलिखित तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे :-

फलों की विभिन्न किस्मों को उगाकर उनका प्रदर्शन, आम के पुराने बागों का जीर्णोद्धार, आम के बागों में गुच्छा. मुच्छा रोग की रोकथाम, आम, चीकू व लीची के बागों में चंदवा प्रबन्धन; कैनोपी मैनेजमैन्ट सुक्ष्म सिंचाई द्वारा सिंचाई व उर्वरक प्रदान करना, फलों की तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन व किसानों, कर्मचारियों, अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना इत्यादि। इस समय केंद्र पर आम, लीची एवं सेब की किस्मों पर फलों की तुड़ाई का कार्य चल रहा है जोकि विभाग द्वारा प्रतिवर्ष नीलामी के माध्यम से किया जाता है। इस समय आम की दशहरी, लंगड़ा, चौसा, रामकेला एवं आम्रपाली जैसे परम्परागत किस्मों के साथ साथ पूसा अरुणिमा, अम्बिका, अरुणिका, पूसा सूर्या, पूसा पीताम्बर, दूधपेड़ा, ऑस्टिन, केसर ठथाई मैंगो जैसी उन्नत किस्मों पर आम के फल किसानों के आकर्षण का केंद्र बने हुए है। किसानों को प्रदर्शन के लिए आम के फलों की गुणवत्ता में सुधार एवं रोगों से मुक्त रखने के लिए प्रयोग की दृष्टि से बैगिंग तकनीक अपनाई गई है। इसके साथ साथ केंद्र पर 1 एकड़ में लीची एवं 0.5 एकड़ क्षेत्र में स्थापित सेब की फसल पर भी भरपूर फल देखने के को मिल रहा है। लीची का बाग लगभग 40 वर्ष

पुराना है जिस को कैनोपी मैनेजमेंट तकनीक से उचित प्रबंधन करके अधिक पैदावार प्राप्त की जा रही है।

किसान भाइयों को फलों की उन्नत किस्मों के कमली पौधे उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र पर नर्सरी स्थापित की गई है जिसके माध्यम से प्रतिवर्ष विभिन्न फल फसलों की उच्च गुणवत्ता के लगभग 80 हजार से 1 लाख कलमी पौधे तैयार करके किसानों को न्यूनतम दरों पर उपलब्ध करवाए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त इस केन्द्र पर किसानों को बागवानी क्षेत्र के प्रति जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष निशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमे एक दिवसीय, साप्ताहिक व 200 घण्टे के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। केंद्र द्वारा अभी तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 2257 किसानों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस वर्ष (2025-26) के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के वार्षिक कैलेंडर को शीघ्र ही समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा। इस प्रकार उप उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र, लाडवा (कुरुक्षेत्र) ने निरंतर किसानों को तकनीकी सहयोग एवं रियायती दरों पर फलों की उन्नत किस्मों की रोपण सामग्री उपलब्ध करवाकर उनकी आय में वृद्धि के लिए नए अवसर प्रदान कर-के प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों के किसानों के लिए एक प्रेरणा स्त्रोत के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई है जिसकी सराहना समय समय पर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।

संपादकीय

न्यायिक जवाबदेही हेतु स्वतंत्र निगरानी, पारदर्शी परिसंपत्ति घोषणा और नियमित कार्यप्रणाली समीक्षा जरूरी

जी हां हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश पर वित्तीय कदाचार के आरोपों के बाद केंद्र सरकार द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पर विचार, भारत में न्यायिक उत्तरदायित्व की वास्तविकता और प्रभावशीलता को लेकर एक नई बहस को जन्म देता है। यह मामला न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है, बल्कि यह न्यायपालिका की आंतरिक पारदर्शिता, जवाबदेही और स्व-नियमन के तंत्र की सीमा रेखा भी स्पष्ट करता है।आइये समझते हैं भारत में न्यायिक उत्तरदायित्व की वर्तमान व्यवस्था के बारे में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने हेतु 'न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968' लागू है। इसमें किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग के लिये 100 लोकसभा या 50 राज्यसभा सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। इसके बाद एक जांच समिति दोष सिद्ध होने पर संसद में दो-तिहाई बहुमत से अनुमोदन प्राप्त करती है।

हालांकि, अब तक इस प्रक्रिया में प्रभावशीलता का अभाव दिखा है। 1993 में जस्टिस वी. रामास्वामी के मामले में यह प्रक्रिया अधूरी रह गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक आंतरिक तंत्र बनाया है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश या संबंधित उच्च न्यायालय के सी जे आई शिकायतों की प्रारंभिक जांच करते हैं। यदि शिकायत उचित पाई जाए, तो एक आंतरिक समिति इसकी विस्तृत जांच करती है। परंतु, इसमें पारदर्शिता और कानूनी अधिकार की कमी है। न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 (विफल प्रयास) विधेयक का उद्देश्य न्यायिक आचरण पर निगरानी रखने के लिये एक स्वतंत्र निकाय 'राष्ट्रीय न्यायिक निरीक्षण समिति' की स्थापना करना था। यह विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, पर राज्यसभा में अटक गया। वर्तमान में न्यायाधीशों के आचरण पर निगरानी हेतु कोई स्वतंत्र वैधानिक निकाय नहीं है। अधिकांश मामलों में न्यायाधीशों का त्यागपत्र या आंतरिक जाँच ही अंतिम उपाय बन जाता है, जिससे पारदर्शिता की कमी बनी रहती है। न्यायिक उत्तरदायित्व की अनिवार्यता के कारणों की बात करें तो अत्यधिक स्वतंत्रता के कारण न्यायपालिका बाह्य जाँच से प्रायः बच जाती है। इसीलिए जब गंभीर आरोप भी लगे हों, तब भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता, जिससे 'दंड से छूट' की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव नियुक्तियों पर सवाल खड़े करता है। इससे वंशवाद और पक्षपात की आशंका भी प्रबल होती है। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश न्यायिक पारदर्शिता में सुधार लाकर स्वतंत्र निरीक्षण निकाय स्थापित कर चुके हैं, जबकि भारत इस दिशा में पिछड़ रहा है। कुछ मामलों में न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती दिखाई देती है, जिससे उसकी जवाबदेही पर प्रश्न उठते हैं। आइये देखते हैं इस पूरे प्रकरण में चुनौतियाँ और संभावित जोखिमों को। यदि उत्तरदायित्व का ढांचा राजनीतिक हस्तक्षेप से युक्त हो, तो यह न्यायिक निष्पक्षता को कमजोर कर सकता है। हाल ही में लोकपाल द्वारा न्यायाधीशों को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने के प्रयास इसी बहस का हिस्सा रहे हैं।महाभियोग जैसे तंत्र राजनीतिक दलों की रणनीति का शिकार हो सकते हैं। जैसे कि 1993 में जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ प्रस्ताव लोकसभा में राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति के चलते विफल हो गया था। अगर न्यायाधीशों के खिलाफ बार-बार जाँच या आरोप लगते हैं, तो इससे आमजन में न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और निष्पक्षता पर प्रभाव पड़ सकता है। भिन्न-भिन्न अदालतों में न्यायिक कदाचार से निपटने के अलग-अलग तरीके हैं। इससे निष्पक्षता और पारदर्शिता की भावना को चोट पहुँचती है। संभावित समाधान और सुधार के उपाय भी हैं। एक वैधानिक संस्था—'राष्ट्रीय न्यायिक निरीक्षण समिति'—जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश, विधि विशेषज्ञ और बाहरी प्रतिष्ठित व्यक्ति हों, न्यायिक आचरण पर निगरानी रखे। सभी न्यायाधीशों को अपनी और अपने परिजनों की परिसंपत्तियों का वार्षिक खुलासा करना अनिवार्य किया जाए। इससे न्यायपालिका पर विश्वास बढ़ेगा। समीक्षा प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए। साथ ही जांच के दौरान मीडिया और जनता को सूचित किया जाए। इन-हाउस प्रक्रिया के तहत की गई जाँच के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया जाए ताकि निष्पक्षता सिद्ध हो सके। एक व्यापक आचार संहिता, जिसे एक स्वतंत्र संस्था लागू करे, न्यायाधीशों के आचरण हेतु सुसंगत मानक निर्धारित करेगी।न्यायाधीशों की कार्यप्रणाली, निर्णयों की गुणवत्ता, और नैतिक आचरण की नियमित समीक्षा आवश्यक है, जिससे सुधार की संभावनाएँ बनी रहें। जिन कर्मचारियों या हितधारकों को न्यायिक कदाचार की जानकारी हो, उन्हें संरक्षण मिलना चाहिए ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपनी बात रख सकें। अंत में कह सकते हैं कि भारत में न्यायिक उत्तरदायित्व को लेकर वर्तमान तंत्र सीमित, अपारदर्शी और राजनीतिक रूप से प्रभावित रहा है। स्वतंत्र निगरानी निकाय, पारदर्शी परिसंपत्ति घोषणा और न्यायिक कार्यप्रणाली की नियमित समीक्षा जैसे ठोस सुधार अब समय की मांग हैं। ये न केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखेंगे, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा—जनता के विश्वास—को भी मजबूत बनाएंगे। जैसा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा था: 'सच्ची न्यायिक स्वतंत्रता किसी गलत आचरण को ढकने का आवरण नहीं, बल्कि संवैधानिक मूल्यों की पूर्ति का माध्यम है।'

आज का राशिफल

मेष: आज आपको विवादों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, अन्यथा आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। अपनी भूलों को स्वीकार करके उन्हें सुधारना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। स्वार्थी मित्रों से सावधान रहें क्योंकि वे आपको परेशान कर सकते हैं। यात्रा टालना बेहतर होगा। जीवनसाथी की तबीयत थोड़ी खराब रह सकती है।

वृषभ: घर में सुख-शांति बनी रहेगी और पारिवारिक उलझनों से राहत मिलेगी। आप योजनाबद्ध ढंग से अपने कार्य पूरे करेंगे। व्यवसाय में अचानक धन लाभ की संभावना है। किसी नए और बड़े कार्य की शुरूआत के लिए दिन अनुकूल है। हालांकि, किसी भी काम को जल्दबाजी में न करें।

मिथुन: आपकी मेहनत और कार्यशैली की सराहना होगी। पुरानी कोई समस्या अब सुलझ सकती है। काम का दबाव होने के बावजूद आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। सहयोगियों पर विश्वास बनाए रखें। नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं।

कर्क: आपको अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिलेंगे, लेकिन लापरवाही से उन्हें गंवा सकते हैं। प्रेम संबंधों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अनावश्यक यात्राओं से बचें क्योंकि इससे समय नष्ट हो सकता है। बच्चों से संवाद करें, इससे उनकी परेशानियों को समझने में मदद मिलेगी।

सिंह: आज आप दिखावे में अधिक खर्च कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में कार्यों को जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रति सकारात्मक भाव रखेंगे। भविष्य को लेकर कुछ असमंजस रह सकता है। शुभचिंतकों की बातों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि आपका आत्मबल थोड़ा कमजोर हो सकता है।

कन्या: कोई शुभ कार्य या आयोजन तय हो सकता है। व्यवसाय में आर्थिक लाभ के योग हैं। बेरोजगारों को नौकरी मिलने की संभावना है जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। विद्यार्थी जटिल समस्याओं को हल कर सकेंगे।

तुला: कामकाज को लेकर आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है। करियर से जुड़े निर्णयों में बुजुर्गों की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। घरेलू कार्यों में समय ज्यादा लगेगा। व्यवसाय में कुछ अड़चनों का सामना हो सकता है। कानूनी मामलों को लेकर तनाव संभव है। व्यर्थ की चिंताओं से दूर रहें।

वृश्चिक: आप पूरे जोश और ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे। रहस्यमय विषयों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखेंगे। साझेदारी वाले कामों में लाभ होगा। मानसिक शांति के लिए एकांत का सहारा लेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

धनु: किसी पारिवारिक सदस्य को लेकर चिंता हो सकती है। वैवाहिक जीवन में तनाव की संभावना है। बच्चों को सिरदर्द की शिकायत हो सकती है। महिलाओं को सेहत संबंधी दिक्कत आ सकती है। खर्चों में इजाफा होगा।

मकर: शेयर बाजार से लाभ के संकेत मिल रहे हैं। कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। मनचाही इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। आर्थिक लेन-देन में सतर्क रहें। सरकारी कामों की रुकावटें दूर होंगी। आप नए कार्यों में रुचि ले सकते हैं।

कुंभ: आप अपने आत्मसम्मान को लेकर सजग रहेंगे। तकनीकी क्षेत्रों में आर्थिक लाभ संभव है। लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल है। अपनी रुचियों के अनुसार काम करने से संतोष और लाभ मिलेगा।

मीन: कारोबार में अच्छा मुनाफा हो सकता है। दोस्तों के माध्यम से शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। गैरकानूनी गतिविधियों से दूर रहना आवश्यक है। वाहन चलाते समय सतर्क रहें।

भारत की बहुआयामी प्रगति, समृद्धि और सम्मान के 11 वर्ष

डॉ मोहन यादव (हि.स.)

नये भारत निर्माण के दृष्टा, वैश्विक राजनेता और हमारे मार्गदर्शक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के 11 वर्षों का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिये समर्पित रहा है। यह समय अनूठा, अद्भुत और अकल्पनीय है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को विश्व में मान, सम्मान और श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। इस विशेष उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई।

प्रधानमंत्री जी की यह यात्रा देश की बहुआयामी प्रगति, समृद्धि और सम्मान की यात्रा है। इसमें एक ओर भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बना है, देश का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़ा है और भारत अब डिफेंस इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर बन गया है। वहीं 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आये हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार का लाभ मध्यप्रदेश और प्रदेशवासियों को मिल रहा है। इस विशेष संयोग में प्रदेश ने नवाचारों के साथ विकास के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सम्मान का मंत्र दिया। उन्होंने इन्हीं चार स्तंभों के समग्र विकास से वर्ष 2047 तक विकसित भारत निर्माण का मार्ग बताया। हमने इन्हीं स्तंभों पर केन्द्रित मिशन बनाकर कार्य आरंभ कर दिया है। प्रधानमंत्री जी की नीतियों और निर्णयों ने नये आत्मनिर्भर भारत निर्माण को गति दी है। 11 वर्ष पूर्व मोदी जी ने संसद की सीढ़ियों को नमन करके जो संकल्प व्यक्त किये थे, उनमें उनकी भावी यात्रा के साथ नये भारत निर्माण के संकेत भी थे।

उन्होंने निरंतर अपने संकल्पों की सिद्धि के साथ देश को आगे बढ़ाया है और राष्ट्र तथा समाज के उत्थान के लिए अभूतपूर्व निर्णय लिये हैं। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण, भारत में नागरिकता कानून (सीएए) बनाने, तीन तलाक जैसे अमानवीय कानून को समाप्त करने, वक्फ संपत्ति का मुस्लिम समाज के कल्याण में उपयोग के लिए वक्फ संशोधन विधेयक कानून लाने जैसे निर्णय प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति से ही संभव हुए हैं। उनका दृढ़ संकल्प सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में भी दिखाई दिया। बालाकोट के बाद ऑपरेशन सिंदूर से भारत के सामर्थ्य को पूरी दुनिया ने देखा है। पहलगाम में बहनों के सामने आतंकियों ने उनका सिंदूर मिटाया था, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से यह साबित कर दिया कि यह नया भारत है जो राष्ट्र के सम्मान, नागरिकों की सुरक्षा और मानवता के लिए घर में घुसकर भी मारना जानता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल की यह समृद्ध यात्रा राष्ट्र की उन्नति, आधारभूत समस्याओं के निराकरण और वैश्विक छवि के उत्थान की रही है। देश के 80 करोड़ से अधिक गरीबों को निःशुल्क अन्न, 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्का घर, हर घर में शौचालय, 15.6 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल, 10 करोड़ से अधिक घरों में उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन और गांवों को रोशन किया है। उनके स्वच्छ भारत अभियान के आह्वान पर पूरा देश स्वच्छता एवं साफ सफाई में जुट गया। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के इंदौर को लगातार सात बार स्वच्छ शहर का पुरस्कार और मध्यप्रदेश को दूसरा सबसे स्वच्छ राज्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ।

प्रधानमंत्री जी ने 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' का उद्घोष किया। उनकी नीतियों में अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति के कल्याण की अवधारणा है। सबके स्वस्थ और सुखमय जीवन के लिए 'आयुष्मान भारत' अभियान चलाया। इसमें 9 करोड़ से अधिक लोगों का मुफ्त उपचार हुआ है। सत्तर वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को भी निःशुल्क उपचार मिला है। 16 हजार से अधिक जन औषधि केन्द्रों से सस्ती और अच्छी दवाएं उपलब्ध करवाई है। कोरोना काल में देशवासियों को आपदा में अवसर का मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत निर्माण का संकल्प दिया और देशवासियों को स्वदेशी निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाई। इस भारतीय वैक्सीन को दुनिया के कई देशों ने भी स्वीकारा। उन्होंने श्रृंखलाबद्ध लोक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं से समाज के हर वर्ग के समग्र विकास की समुचित व्यवस्था की। जनधन योजना से 55 करोड़ से अधिक लोगों को वित्तीय धारा से जोड़ा गया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से गरीबों को 44 लाख करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है। पीएम स्वनिधि और स्ट्रीट वेंडर से रेहड़ी-पटरी के व्यवसायियों को आधार दिया और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी, युवा शक्ति को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए, नई शिक्षा नीति के साथ 1.6 करोड़ से अधिक युवाओं का कौशल विकास और 1.6 लाख से अधिक स्टार्टअप्स शुरू कर युवाओं को विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति के लिये भागीदार बनाया है। मध्यप्रदेश ने सबसे पहले नई शिक्षा नीति को अमल में लाया और युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर रोजगार तथा स्व-रोजगार के लिये अनंत संभावनाए विकसित की हैं।

मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 7.7 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड तथा फसल बीमा से अन्नदाताओं को संबल मिला है। महिलाओं की सुरक्षा के उपाय, आर्थिक स्वावलंबन, सामाजिक उत्थान और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है। देशभर में लगभग 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। देश में 90 लाख से अधिक स्व सहायता समूहों के माध्यम से 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं लाभान्वित हुई हैं इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश में लगभग 5 लाख स्व सहायता समूहों से 62 लाख महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं।

वर्ष 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी। प्रधानमंत्री जी की आर्थिक नीतियों, विशेषकर नोटबंदी जिससे कदाचार पर नियंत्रण हुआ, डिजिटलाइजेशन और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) से ऑनलाइन लेनदेन का चलन बढ़ा। इन सभी नीतियों ने आर्थिक विकास के निर्णयों को सबल किया और भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया।

प्रधानमंत्री जी ने विकास के साथ विरासत का आह्वान किया है। विरासत को सहेजने के लिए उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास और पुनर्प्रतिष्ठा का कार्य आरम्भ किया तथा इसे धार्मिक पर्यटन से जोड़ा। लोगों का अपनी विरासत के प्रति सम्मान बढ़ने के साथ पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है। नमामि गंगे योजना से पवित्र नदियों की सफाई अभियान के साथ जल संरक्षण की परम्परा विकसित हो रही है।

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने मध्यप्रदेश में विकास के साथ विरासत के संकल्प को आत्मसात किया और भव्य और दिव्य महाकाल महालोक का निर्माण किया। श्रीराम वन गमन पथ, श्रीकृष्ण पाथेय निर्माण और विक्रमोत्सव का आयोजन किया है। प्रदेश को केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल रिवर लिंक परियोजनाओं की सौगात मिली है। आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए श्री मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल और ग्लोबल का आह्वान किया। मध्यप्रदेश में हमने प्रत्येक क्षेत्र के विशिष्ट उत्पादों के अनुरूप उद्योग स्थापित करने का नवाचार प्रारंभ किया है। इसके लिए पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव फिर महानगरों और विदेशों में रोड शो तथा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की सफलता के बाद अब सेक्टर आधारित समिट के विस्तार का उपक्रम शुरू किया है। इससे प्रदेश के औद्योगिक विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन आयेगा।

श्री मोदी जी ऐसे युगदृष्टा हैं जिन्होंने आधारभूत समस्याओं के समाधान और विरासत को सहेजने के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की भी नई उड़ान भरी है। उन्होंने स्वदेशी तकनीक विकसित करने का आह्वान किया था जिसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। प्रधानमंत्री जी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र (इसरो) के वैज्ञानिकों से स्वयं चर्चा की और आवश्यक बजट तथा सुविधाएं उपलब्ध करवाई। इसका परिणाम यह है कि भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान तकनीक विश्व में अग्रणी बनी और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया।कनेक्टिविटी से विकास को गति प्रदान करने के लिये प्रधानमंत्री जी ने सड़क और रेल नेटवर्क का विस्तार, 23 शहरों में मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति, बंदरगाह, हवाई मार्ग, हाई स्पीड कॉरिडोर निर्माण के लक्ष्य को स्वरूप प्रदान किया है। अटल टनल और दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज चेनाब आकार ले चुका है।

प्रधानमंत्री जी का संकल्प है स्वतंत्रता के 100वें वर्ष यानी वर्ष 2047 तक भारत को 35 ट्रिलियन डॉलर की पूर्ण विकसित अर्थव्यवस्था बनाना और विश्व की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना है। इस संकल्प की पूर्ति में मध्यप्रदेश सहभागी बनने के लिये प्रतिबद्ध है। उनके आशीर्वाद और सहयोग से मध्यप्रदेश प्रगति के साथ नया इतिहास रच रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नये भारत निर्माण लक्ष्य को सार्थक करने में मध्यप्रदेश की अग्रणी भूमिका रहेगी।

(लेखक, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।)

प्रधानमंत्री मोदी के सेवा, सुशासन और समर्पण के ग्यारह वर्ष

सुनील कुमार तिवारी (हि.स.)

साल 2014 में जब नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब देश एक निर्णायक नेतृत्व की तलाश में था। आर्थिक अनिश्चितता, नीतिगत पंगुता और भ्रष्टाचार के मामलों ने जनता को निराश कर दिया था। ऐसे समय में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय मंच पर एक उम्मीद की किरण बनकर उभरे। एक चाय बेचने वाले से लेकर देश के शीर्ष नेतृत्व तक का उनका सफर न केवल प्रेरणादायक रहा है, बल्कि यह उस विश्वास और प्रतिबद्धता की कहानी है जो उन्होंने देश की जनता के साथ साझा की। पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। चाहे वह आधारभूत ढांचा हो, आर्थिक विकास, गरीब कल्याण, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, युवाओं का सशक्तिकरण या फिर वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 11 वर्ष के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है- भ्रष्टाचार से मुक्त शासन। इतने लंबे समय तक शीर्ष पद पर रहने के बावजूद मोदी पर व्यक्तिगत स्तर पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, जो भारतीय राजनीति में एक दुर्लभ उपलब्धि है। उनके नेतृत्व में सरकार ने "न खाऊंगा, न खाने दूंगा" के सिद्धांत पर चलते हुए प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यक्षमता को प्राथमिकता दी। एक और उल्लेखनीय पहल यह रही कि मोदी सरकार ने राजनीतिक स्थिरता के साथ निर्णायक शासन का उदाहरण प्रस्तुत किया। तीन बार लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर नरेन्द्र मोदी ने यह साबित किया कि यदि नेतृत्व जनविश्वास अर्जित कर सके तो लोकतंत्र में लंबी स्थिरता संभव है।

गरीबों का सशक्तिकरण और जनकल्याण योजनाएं

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई): गरीबों को पक्के मकान देने के वादे को जमीन पर उतारते हुए सरकार ने अब तक 4 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण किया है। यह योजना विशेष रूप से महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देती है, जिससे महिला सशक्तिकरण को भी बल मिला।

उज्ज्वला योजना: आठ करोड़ से अधिक बीपीएल परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देकर सरकार ने न केवल महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम उठाया, बल्कि स्वच्छ ईंधन के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया।

जल जीवन मिशन: हर घर जल अभियान के तहत 14 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल की सुविधा पहुंचाई गई। इससे न केवल ग्रामीण महिलाओं को राहत मिली, बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार भी हुआ।

स्वच्छ भारत मिशन: साल 2014 में खुले में शौच मुक्त भारत का सपना देखते हुए शुरू किए गए इस मिशन के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ। यह न केवल स्वच्छता की दिशा में क्रांति साबित हुई, बल्कि सामाजिक गरिमा का प्रतीक भी बनी।

डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजिकल क्रांति: डिजिटल इंडिया केवल एक अभियान नहीं रहा, यह देश की अर्थव्यवस्था और प्रशासन में क्रांतिकारी बदलाव का आधार बना।

यूपीआई क्रांति: मार्च 2025 में अकेले 1,830 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए जिनका मूल्य 24.77 लाख करोड़ रुपये रहा। यह विश्व स्तर पर भारत की अग्रणी स्थिति को दर्शाता है।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी): अब तक 30 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी गई, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हुआ।

दूरसंचार विस्तार: देश के हर कोने में 4जी और अब 5जी नेटवर्क की पहुंच, ग्रामीण भारत को डिजिटल रूप से जोड़ने में सफल रही है।

बुनियादी ढांचे में क्रांति: प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा फोकस रहा है-विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे का निर्माण।

राजमार्ग निमार्ण: 2014 के बाद से अब तक 90,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ।

रेलवे आधुनिकीकरण: 100 से अधिक रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया गया, बुलेट ट्रेन परियोजना पर कार्य चल रहा है, और वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों की शुरूआत हुई है।

एयरपोर्ट निमार्ण: यूडीएएन योजना के तहत छोटे शहरों को हवाई संपर्क से जोड़ा गया। अब देश में 150 से अधिक एयरपोर्ट्स कार्यरत हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल: 2014 की तुलना में आधारभूत परियोजनाओं के लिए आवंटित बजट में पांच गुना से अधिक की वृद्धि की गई है।

आत्मनिर्भर भारत और आर्थिक विकास

कोरोना महामारी के दौरान घोषित "आत्मनिर्भर भारत अभियान" केवल एक नारा नहीं था, बल्कि एक व्यापक दृष्टिकोण था जिसमें उत्पादन, नवाचार, निर्यात और रोजगार सभी शामिल थे।

मेक इन इंडिया: देश अब रक्षा, मोबाइल, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल, और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है।

विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था: साल 2014 में भारत 11वीं अर्थव्यवस्था था, आज वह चौथे पायदान पर है, और जल्द ही तीसरे स्थान पर आने की संभावना है।

स्टार्टअप इंडिया: आज भारत में एक लाख से अधिक स्टार्टअप हैं जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। यह नवाचार और उद्यमिता का नया युग है।

कृषि और ग्रामीण विकास

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान): 12 करोड़ से अधिक किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है। अब तक 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों को दी जा चुकी है।

फसल बीमा योजना: इस योजना ने किसानों की आय को सुरक्षित किया है। करोड़ों किसानों को बीमा दावों के तहत हजारों करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

ई-नाम: कृषि उपज का डिजिटल व्यापार, किसानों को पारदर्शी कीमतें और बेहतर बाजार उपलब्ध कराने का एक बड़ा माध्यम बना है।

युवा शक्ति और शिक्षा: भारत की 65 फीसद आबादी 35 वर्ष से कम है। इस युवा शक्ति को उत्पादक बनाना मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है।

स्किल इंडिया: 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है।

स्टार्टअप और स्टैंडअप इंडिया: युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन हुआ।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: यह नीति भारत की शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों पर ले जाने का प्रयास है, जिसमें व्यावहारिकता, नवाचार और मातृभाषा में शिक्षा को महत्व दिया गया है।

महिलाओं का सशक्तिकरण

मोदी सरकार का महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान रहा है। इनमें प्रमुख हैं-बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। महिला जनधन खाते। मातृत्व वंदना योजना। कार्यस्थलों पर सुरक्षा और समान अवसर। इन योजनाओं से महिलाओं की भागीदारी शिक्षा, अर्थव्यवस्था और शासन में बढ़ी है।

वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति निश्चय तौर पर प्रगतिशील रही है। इसके उदाहरण हैं- जी20 की अध्यक्षता और सफल शिखर सम्मेलन। क्वाड, ब्रिक्स और एससीओ में सक्रिय भागीदारी। प्राकृतिक आपदाओं में अंतरराष्ट्रीय सहायता। भारतीय प्रवासी समुदाय से जुड़ाव।प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं और सक्रिय कूटनीति ने भारत को वैश्विक नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका दिलाई है।

इससे संस्कृति, धर्म और विरासत का पुनर्जागरण हुआ है। मोदी सरकार ने सांस्कृतिक मूल्यों के पुनरुद्धार को नया आयाम दिया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक, राम मंदिर निर्माण लोक की जनभावना के तहत कराया गया। बौद्ध तीर्थ स्थलों का विकास और बुद्ध धम्म को वैश्विक मंच पर स्थापित कराया गया। प्राचीन ग्रंथों और धरोहरों का डिजिटलीकरण भी अहम है। आयुष मंत्रालय की स्थापना और योग का वैश्वीकरण महानतम उपलब्धि है।

खेल और फिट इंडिया अभियान

खेलो योजना: ग्रामीण व शहरी प्रतिभाओं को आगे लाना।

टॉप्स स्कीम: ओलंपिक संभावित खिलाड़ियों को पोषण, ट्रेनिंग और वित्तीय सहायता।

पैरालंपिक सफलता: भारत ने हाल के पैरालंपिक्स में रिकॉर्ड 29 पदक जीते हैं।

फिट इंडिया मूवमेंट: लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता।

कोरोना काल का प्रभावी प्रबंधन

कोविड-19 एक अभूतपूर्व वैश्विक संकट था। भारत में 200 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए, "वैक्सीन मैत्री" के तहत 100 से अधिक देशों को टीके भेजे गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिला।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने बीते 11 वर्षों में विकास की अभूतपूर्व यात्रा तय की है। यह यात्रा केवल आंकड़ों और परियोजनाओं की नहीं है, बल्कि यह उस परिवर्तन की कहानी है जिसने गरीब से लेकर अमीर, किसान से लेकर युवा, ग्रामीण से लेकर शहरी और महिला से लेकर दिव्यांग तक सभी को मुख्यधारा में शामिल किया है। आज जब भारत 2047 में आजादी के 100 वर्ष पूरे होने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, तब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की नीति, नीयत और नेतृत्व इस परिवर्तन की धुरी बन चुकी है। एक नए भारत की नींव रखी जा चुकी है-विकसित, आत्मनिर्भर, समावेशी और वैश्विक भारत की।

लेखक, भारत सरकार के पत्र एवं सूचना कार्यालय से संबद्ध हैं।)

तहसीलों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में अग्रसर है पंजाब: भगवंत मान

जो लोग सोचते थे कि उनके पास लूट का दैवीय अधिकार है, वे अब अप्रासंगिक हुए, पटियाला के शासक केवल अपने विकास के लिए परेशान थे

संवाददाता
दूधन साधां (पटियाला)

पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार के अथक प्रयासों के कारण पूरे पंजाब की सभी तहसीलें और उप-तहसील कॉम्प्लेक्स भ्रष्टाचार मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ नवनिर्मित तहसील कॉम्प्लेक्स को जनता को समर्पित करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि जब राज्य सरकार ने कार्यभार संभाला था, तब राजस्व अधिकारी सोचते थे कि उनके पास भ्रष्टाचार के माध्यम से लोगों को लूटने का दैवीय अधिकार है। उन्होंने कहा कि वे आम लोगों को छोटे-मोटे कामों के लिए भी परेशान करते थे और यदि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती थी, तो काम में अड़चन डालने की धमकी देते थे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का वादा करके सत्ता में आई है, जिसके कारण राज्य सरकार ने इसके खिलाफ व्यापक कार्रवाई शुरू की है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप पूरे पंजाब की सभी तहसीलें और उप-तहसील कॉम्प्लेक्स भ्रष्टाचार मुक्त होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी सामूहिक छुट्टियों या हड़तालों के बहाने आम लोगों को परेशान करते थे, लेकिन राज्य सरकार इन भ्रष्ट अधिकारियों के सामने नहीं झुकी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ह्यआपह्ण सरकार भ्रष्टाचार के प्रति बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं रखती और इन अधिकारियों की ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं किया गया, साथ ही भ्रष्ट और अहंकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि इन अधिकारियों के विरोध प्रदर्शनों से सख्ती से निपटा गया, क्योंकि वे भ्रष्टाचार का लाइसेंस लेना चाहते थे, जिसकी किसी भी कीमत पर अनुमति नहीं दी जा सकती। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब इन भ्रष्ट तहसीलदारों को भ्रष्टाचार की पूरी श्रृंखला तोड़ने के लिए एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्होंने भ्रष्टाचार की तुलना कैंसर की घातक बीमारी से करते हुए कहा कि कीमोथेरेपी (सख्त कार्रवाई) ही इसका एकमात्र इलाज हो सकता है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने जमीन के दस्तावेजों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल कर दिया है, जो आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करता है, निजी वसीका नवीसों पर निर्भरता कम करता है, और नागरिकों को अपने लेन-देन स्वयं करने का अधिकार देता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब लोगों को भुगतान के लिए बैंकों में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन एकीकृत भुगतान प्रणाली सभी आवश्यक शुल्क, जैसे स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क, को एक ही डिजिटल लेन-देन में भुगतान करने की अनुमति देती है। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि यह प्रणाली डिमांड ड्राफ्ट या नकदी प्रबंधन की आवश्यकता को समाप्त करती है और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करती है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का परिणाम है, जिसके कारण उन्होंने पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कार्यभार संभालने के पहले दिन से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ ह्यजीरो टॉलरेंसह्ण नीति अपनाई है। इस नेक कार्य के लिए पंजाबियों से पूर्ण सहयोग और दिल से समर्थन की मांग करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि आने वाले समय में भी इस अभियान को सफल बनाना बहुत जरूरी है।

पटियाला के शाही परिवार पर तीखा हमला करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि पटियाला और इसके आसपास का क्षेत्र पुराने शासकों के संकीर्ण हितों और लालच के कारण विकास के मामले में पिछड़ गया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों ने शहर की बदहाली की कीमत पर अपने महल बनाए। उन्होंने कहा कि यह हास्यास्पद है कि सत्ता में बैठे ह्यमहाराजाह्ण शहर के विकास से ज्यादा अपने विकास को लेकर चिंतित थे। भगवंत मान ने अफसोस जताया कि पटियाला से आए पंजाब के शासकों ने शहर के विकास को पूरी तरह से अनदेखा किया।

मुख्य मंत्री ने कहा कि पारंपरिक राजनीतिक पार्टियां उनसे नाराज हैं, क्योंकि वे यह पचा नहीं पा रही हैं कि साधारण घरों से निकला कोई व्यक्ति राज्य की सत्ता को प्रभावी ढंग से चला रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों का पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों के जनविरोधी और पंजाब विरोधी रवैये के कारण उनसे विश्वास उठ गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य के समझदार और बहादुर लोगों ने 2022 के विधानसभा चुनावों में इन पार्टियों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया और ह्यआपह्ण को भारी बहुमत दिया।

मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्य में विकास नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि राज्य के लोगों ने एक ईमानदार सरकार चुनी है, जो लोगों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को भ्रष्ट और अवसरवादी नेताओं को चुनना पड़ता था, जो उनका एकमात्र विकल्प था। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य ने आम लोगों के लिए नागरिक-केंद्रित सेवाओं की सुचारू और निर्बाध डिलीवरी के एक नए युग की शुरूआत की है।

मुख्य मंत्री ने दोहराया कि अकाली नेताओं ने पैसे के लालच के कारण शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एस.जी.पी.सी.) को केवल ह्यशिरोमणि गोलक प्रबंधक कमेटीह्ण बना दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बादलों ने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए अपनी राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग किया, जिसमें अपने निजी हितों के लिए श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदारों की नियुक्ति में हेरफेर करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि वित्तीय लालच के कारण अकालियों ने एस.जी.पी.सी. की पवित्रता को नष्ट किया और संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए एस.जी.पी.सी. और श्री अकाल तख्त साहिब दोनों का दुरुपयोग किया।

मुख्य मंत्री ने महिलाओं से आगे आकर राजनीति में हिस्सा लेने का आह्वान किया, ताकि वे निर्णय लेने और नीति निर्माण में सक्रिय भागीदार बन सकें और समाज में अत्यंत आवश्यक बदलाव ला सकें। उन्होंने कहा कि आजकल लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से आगे हैं, लेकिन राजनीति में अभी भी उन्होंने नाम नहीं कमाया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र को पहले पुरुषों का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब समय आ गया है जब महिलाओं को इस क्षेत्र में भी बढ़-चढ़कर आगे आना चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि समानता वाले समाज की रचना और समाज व राज्य के व्यापक हित के लिए इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि राज्य के 54,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि सभी नौकरियां बिना किसी भ्रष्टाचार या भाई-भतीजावाद के पूरी तरह से योग्यता के आधार पर दी गई हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इससे युवा पंजाब के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बन रहे हैं। इससे पहले कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने मुख्य मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया।

मान सरकार बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध

संवाददाता
चंडीगढ़

मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार बच्चों के कल्याण और सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अनाथ और बेसहारा बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया किशोर न्याय अधिनियम-2015 के अनुसार कानूनी तरीके से पूरी की जाए, ताकि बच्चों को एक सुरक्षित, प्यार भरा और सम्मानजनक वातावरण मिल सके। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि 0 से 18 साल तक के हर बच्चे के जीवन की रक्षा करना और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं उपलब्ध कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हर बच्चा सुरक्षित, प्यार भरे और सम्मानजनक वातावरण का हकदार है। इसलिए यह आवश्यक है कि गोद लेने की प्रक्रिया हमेशा कानूनी तरीके से की जाए ताकि बच्चे के भविष्य, उसके अधिकारों और कानूनी सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा सके।

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि अक्सर यह देखने में आया है कि अविवाहित माताएं या ऐसे माता-पिता जो बच्चों को अपने पास रखने में

डॉ. बलजीत कौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया कानूनी तरीके से सुनिश्चित की जाए

असमर्थ हैं और बच्चों को सौंपना या गोद देना चाहते हैं, वे सबसे पहले अस्पताल, नर्सिंग होम या डॉक्टर से संपर्क करते हैं। इसके अलावा, जो माता-पिता बच्चों को गोद लेना चाहते हैं, वे भी इन्हीं से संपर्क करते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं (सरकारी/निजी) और डॉक्टर काम कर रहे हैं, उन्हें बच्चे को सौंपने या गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी होना जरूरी है, ताकि किसी भी तरह के अवैध गोद लेने को रोका जा सके और बच्चों के हितों की रक्षा करते हुए उन्हें तस्करी या शोषण के जोखिमों से बचाया जा सके।

गोद लेने की प्रक्रिया को गंभीरता से लेते हुए, जारी निदेर्शों का पालन करने के लिए डॉ. बलजीत कौर ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों को हिदायत दी कि यदि उनके पास ऐसे माता-पिता/बच्चे आते हैं, तो उनकी जानकारी 24 घंटे के भीतर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098/निकटतम पुलिस स्टेशन/बाल कल्याण कमेटी/जिला बाल संरक्षण इकाई या पंजीकृत चाइल्ड केयर को दी जाए, ताकि एक कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जा सके।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यदि किसी भी सरकारी या निजी संस्थान द्वारा कानूनी गोद लेने की प्रक्रिया का उल्लंघन किया जाता है और बच्चे को अवैध तरीके से गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है या जानकारी को गुप्त रखा जाता है, तो इस संबंध में उन्हें 6 महीने की सजा या 10 हजार रुपये का जुमार्ना या दोनों सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया की जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि बच्चे को कानूनी तरीके से गोद लेने की जानकारी कारा नई दिल्ली की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

डीएसजीएमसी अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका द्वारा पंजाब में धर्मांतरण पर चिंता व्यक्त

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका ने आज पंजाब के गांवों में सिख धर्म से ईसाई धर्म में हो रहे धर्मांतरण को लेकर गंभीर चिंता जताई है। यहाँ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सभी सदस्यों के साथ बैठक के बाद आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, सरदार कालका ने कहा कि उन्होंने कमेटी के सभी सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्रों में हो रहे किसी भी धर्मांतरण के प्रयासों पर निगरानी रखने और सतर्क रहने का निर्देश दिया है। इस अवसर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव सरदार जगदीप सिंह कहलौं तथा अन्य पदाधिकारी और सदस्य भी उपस्थित थे। रिपोर्टों का हवाला देते हुए सरदार कालका ने कहा, ₹यह चौंकाने वाली बात है कि पंजाब के 12,500 गांवों में से 8,000 गांवों में ईसाई समितियाँ स्थापित हो चुकी हैं और बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। पंजाब में 65,000 ईसाई प्रचारक सक्रिय हैं।₹

ऐसे हालात में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की धर्म प्रचार में विफलता पर सवाल उठते हैं। डीएसजीएमसी ने पंजाब में 'धर्म प्रचार लहर' की शुरूआत की है और हाल ही में 2,500 लोगों ने पूर्ण सिख बनकर अमृत संचार किया है। हमारे पास

एसजीपीसी जितने संसाधन नहीं हैं। श्री कालका ने कहा कि उनके विचार मेंएसजीपीसी को उन लोगों को वापस सिख धर्म में लाने की दिशा में सक्रिय और बड़ी भूमिका निभानी चाहिए, जो अन्य रास्तों पर चले गए हैं।

सरदार कालका के अनुसार, एसजीपीसी के अध्यक्ष सरदार हरजिंदर सिंह धामी धर्मांतरण को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे, लेकिन अफसोस की बात है कि वह जिस पार्टी (शिरोमणि अकाली दल) का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके नेता केवल अन्य सिख संस्थाओं की आलोचना तक ही सीमित हैं।

गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब के बाहर शिरोमणि अकाली दल के नेताओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन पर बात करते हुए, जिसमें सरदार परमजीत सिंह सरना और सरदार मनजीत सिंह जी.के. भी शामिल थे, सरदार कालका ने कहा कि यह प्रदर्शन गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब की मयार्दा के खिलाफ था।

उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में राज्य सरकार द्वारा सदस्यों की नियुक्ति के विरोध में था, इसलिए यह प्रदर्शन सिविल सचिवालय या गुरुद्वारा चुनाव निदेशक के कार्यालय के बाहर किया जाना चाहिए था, न कि सबसे पवित्र स्थल झ गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब के बाहर।

उन्होंने यह भी कहा कि जब से 1971 में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अस्तित्व में आई और 1974 में पहली बार चुनाव हुआ, तथा बाद में 1979, 1995, 2002, 2007, 2013, 2017 और 2021 में चुनाव हुए, तब से सदस्यों की नियुक्ति हमेशा राज्य सरकार द्वारा ही की जाती रही है।

संक्षिप्त-समाचार

भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल आज करेंगे फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल की शुरूआत

चंडीगढ़। विश्वास, पारदर्शी पहुंच और परिवर्तन के नए युग की शुरूआत करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल (10 जून को) फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल की शुरूआत करेंगे, जो निवेशकों को आवेदन करने के 45 दिनों के भीतर सभी जरूरी मंजूरियाँ सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, ह्ये सुधार अंत नहीं हैं, बल्कि एक लहर की शुरूआत है-एक ऐसी लहर, जहाँ कारोबार में आसानी केवल नारा नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक संस्कृति बनती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब हमेशा बहादुरों, नवोन्मेषकों और वीरों की धरती रहा है और अब यह भावना भारत की औद्योगिक क्रांति की अगुवाई करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह हर निवेशक के लिए एक साहसी ऐलान है कि पंजाब अपने नियमों के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ कारोबार के लिए तैयार है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल एक तकनीकी उन्नयन से कहीं अधिक, एक नए औद्योगिक प्रशासन मॉडल की रीढ़ की हड्डी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विवेक को अनुशासन में, देरी को डिजिटल में और उलझनों को स्पष्टता में बदल रही है। उन्होंने कहा कि 45 दिनों के भीतर अनुमतियाँ प्राप्त करने से लेकर लालफीताशाही को समाप्त करने तक, पंजाब की प्रणाली अब सामान्य नहीं रही, बल्कि यह सक्रिय, सटीक और पेशेवर बन गई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि चाहे निवेशक स्टार्टअप संस्थापक हो, वैश्विक समूह या कोई उद्यमी, पंजाब उन्हें सिर्फ वित्तीय प्रोत्साहनों से नहीं, बल्कि ईमानदारी और नीयत से भी जी आया नूं कहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर सुधार-चाहे वह एकीकृत नियामक हो, एकीकृत पोर्टल, डीम्ड अप्रूवल, सैद्धांतिक मंजूरी या सशक्त निगरानी प्रोटोकॉल-का उद्देश्य उद्योगपतियों का विश्वास जीतना और उनके कारोबारी सफर में हर पहलू से समर्थन देना है। उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार के अधिकारी सिर्फ नियंत्रक नहीं, बल्कि सहयोगी की भूमिका निभाएंगे।

केनरा रोबेको एएमसी ने निवेश बस यात्रा शुरू करने की घोषणा की

चंडीगढ़। एसेट मैनेजमेंट कंपनी केनरा रोबेको एएमसी (केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड की निवेश प्रबंधक) ने पंजाब में म्यूचुअल फंड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए निवेश बस यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य आम लोगों को सरल भाषा में म्यूचुअल फंड में निवेश के फायदे, उससे जुड़ी सावधानियां और जरूरी जानकारियां देकर बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। यह बस अपनी यात्रा मोहाली से शुरू होकर अगले 24 दिनों में मोहाली, चंडीगढ़, पंचकूला, पटियाला, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर सहित राज्य के प्रमुख शहरों से गुजरेगी। केनरा रोबेको एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ श्री रजनीश नरूला ने कहा कि निवेश की दुनिया में ज्ञान से कीमती कुछ नहीं होता। एक जागरूक निवेशक न केवल अपने लिए बेहतर फैसले लेता है, बल्कि मजबूत और सक्रिय वित्तीय व्यवस्था के निर्माण में भी योगदान देता है। केनरा रोबेको में हम इसे अपनी जिम्मेदारी मानते हैं कि हम लोगों को म्यूचुअल फंड निवेश के फायदों और संभावनाओं के बारे में शिक्षित करें। उन्होंने आगे कहा कि इसी सोच के साथ हम निवेश यात्रा को पंजाब ला रहे हैं। इसका मकसद लोगों को धन प्रबंधन और म्यूचुअल फंड जैसे विकल्पों के बारे में बेहतर जानकारी देना और उन्हें सोच-समझकर दीर्घकालिक निवेश के लिए प्रेरित करना है। यह बस हर शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर जाकर लोगों से सीधा संवाद करेगी और एक डिजिटल अनुभव केंद्र की तरह काम करेगी, जहां वीडियो और सरल बातचीत के जरिए म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारियाँ दी जाएंगी। मकसद है - लोगों को निवेश के प्रति जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना।

सेंटर पार्टनर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित

चंडीगढ़। प्रदेश में अपने शिक्षा के नेटवर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से क्रैक एकेडमी ने हमीरपुर में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में राज्य भर से आए 70 नए सेंटर पार्टनर्स ने हिस्सा लिया। ट्रेनिंग का उद्देश्य सभी नए सेंटर एक जैसे स्तर की सेवा दे सकें और छात्रों से बेहतर तरीके से जुड़ सकें था। कार्यक्रम में क्रैक एकेडमी के आईटी, मार्केटिंग, एकेडमिक्स, सेल्स, एचआर और स्टूडेंट एनरोलमेंट विभागों की टीमों ने विस्तार से जानकारी दी। लाइव सवाल-जवाब सेशन भी हुए, जिनमें सेंटर पार्टनर्स की परेशानियों को समझ कर उसका हल किया गया। साथ ही, सेंटर प्रबंधन, मार्केटिंग रणनीतियों और स्थानीय जरूरतों के अनुसार संचालन को लेकर भी उपयोगी प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम की खास बात एकेडमी टॉप मैनेजमेंट की भागीदारी थी, जिससे सेंटर पार्टनर्स का हौसला और बढ़ा। क्रैक एकेडमी के फाउंडर और सीईओ नीरज कंसल ने कहा, यह सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं थी, बल्कि एक साझा सोच और लक्ष्य की दिशा में उठाया गया कदम था। जैसे-जैसे हम अपने सेंटर बढ़ा रहे हैं, जरूरी है कि हर पार्टनर एक जैसी गुणवत्ता और सेवाएं दे। हमारा मकसद ऐसा मजबूत नेटवर्क बनाना है, जो हर छात्र को बेहतर सहयोग दे, चाहे वो किसी भी जिले में हो।

आधुनिक सुविधाओं के साथ 1000 बिस्तरों के अपग्रेडेशन को भी दी मंजूरी

'युद्ध नशों विरुद्ध' कैबिनेट सब कमेटी ने 200 काउंसलरों की नियुक्ति और पैनल में निजी मनोचिकित्सकों की नियुक्ति को दी मंजूरी

संवाददाता
चंडीगढ़

'युद्ध नशों विरुद्ध' (नशीले पदार्थों के खिलाफ युद्ध) पर मंत्रिमंडल सब-कमेटी ने सोमवार को नशा पीड़ितों के इलाज के लिए मजबूत व्यवस्था स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए। यह महत्वपूर्ण कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि चल रहा अभियान की सफलता के चलते नशीले पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया है, जिससे इलाज चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, डॉ. बलबीर सिंह, तरूनप्रीत सिंह सोंद, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, प्रमुख सचिव वित्त कृष्ण कुमार, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य कुमार राहुल, डीजीपी पंजाब गौरव यादव और सचिव व्यय वी.एन. जादे उपस्थित थे। बैठक में राज्य के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को मजबूत करके नशा मुक्ति सेवाओं की बढ़ती मांग को संपूर्ण किया गया। सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों और अस्पतालों में इलाज चाहने वाले नशा पीड़ितों की संख्या में कई गुना वृद्धि को देखते हुए, सब-कमेटी ने क्षमता बढ़ाने और चिकित्सा सहायता को बढ़ावा देने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। निर्णयों में छह महीने के लिए अस्थायी आधार पर 200 मनोवैज्ञानिकों की तत्काल भर्ती शामिल है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग को इस बीच स्थायी भर्ती सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, आवश्यकतानुसार विभिन्न जिलों में मनोचिकित्सकों को सूचीबद्ध किया

जाएगा, जिन्हें प्रतिदिन दो घंटे के लिए 3000 रुपये मिलेंगे, जो 1500 रुपये प्रति घंटे की दर से होगा, ताकि नशा छोड़ने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों को आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। सब-कमेटी ने स्वास्थ्य विभाग को सभी आवश्यक स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक सप्ताह के भीतर एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने नशा पीड़ितों के इलाज के लिए बुनियादी ढांचे के विस्तार का विवरण दिया। सरकारी अस्पतालों और नशा मुक्ति केंद्रों में बिस्तरों की संख्या 1000 बढ़ा दी गई है। इसके अलावा, यदि सरकारी केंद्रों की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग हो जाता है, तो निजी नर्सिंग संस्थानों और नशा मुक्ति केंद्रों की सेवाओं का अतिरिक्त 1000 बिस्तरों के लिए उपयोग किया जाएगा, जिसका खर्च सरकार वहन करेगी।

वित्त मंत्री ने 1 मार्च से 8 जून तक 'युद्ध नशों विरुद्ध' अभियान के तहत नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ की गई कड़ी कार्रवाई पर भी अद्यतन जानकारी प्रदान की। अब तक एनडीपीएस के तहत 9580 मामले दर्ज किए गए हैं और 16348 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, जिससे नशीले पदार्थों के व्यापार में शामिल 118 व्यक्तियों की संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया है। इस अवधि के दौरान, अवैध पदार्थों की महत्वपूर्ण मात्रा बरामद की गई है, जिसमें 622 किलोग्राम हेरोइन, 14976 किलोग्राम पोस्त का भूसा, 252 किलोग्राम अफीम, 264 किलोग्राम गांजा और 26,49,847 नशीली गोलियां शामिल हैं। अभियान के बारे में विपक्षी दलों द्वारा व्यक्त की गई शंकाओं के बारे में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब में अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों के दौरान नशीले पदार्थों ने जड़ें जमा ली थीं, जिससे युवा कमजोर हो गए थे। उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं से इस महत्वपूर्ण अभियान का समर्थन करने का आग्रह किया, बजाय इसके कि वे संकीर्ण राजनीति में शामिल हों जो सार्वजनिक कल्याण की उपेक्षा करती है और, इसके विपरीत, नशीले पदार्थों से संबंधित मुद्दों को बढ़ावा देती है। वित्त मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल सब-कमेटी की बैठक, जो लगभग डेढ़ घंटे तक चली, ने 'युद्ध नशों विरुद्ध' मुहिम के दौरान अब तक की गई कार्रवाइयों की समीक्षा की और भविष्य की रणनीतियों को तैयार किया।

'जलता' लॉस एंजिल्स नेशनल गार्ड के दो हजार सैनिकों के हवाले, स्थिति और बिगड़ी

अवैध श्रमिकों की तलाश में कार्यस्थलों पर छापे मारने के बाद सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी

आव्रजन अधिकारियों के रास्ते में आने वाले किसी भी प्रदर्शन को संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ विद्रोह माना जाएगा: ट्रंप

एजेंसी (हि.स.)

लॉस एंजिल्स

कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा शहर लॉस एंजिल्स ट्रंप प्रशासन के आव्रजन छापों के विरोध में 'जल' रहा है। इसे रोकने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजिल्स की सड़कों पर कम से कम 2,000 नेशनल गार्ड सैनिकों को उतारा है। बावजूद इसके स्थिति और और गंभीर होती दिख रही है। लॉस एंजिल्स संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, लॉस एंजिल्स में शनिवार को कानून प्रवर्तन अधिकारियों का सैकड़ों प्रदर्शनकारियों से जूझना पड़ा। अधिकारियों को कुछ रबर की गोलियों, आंसू गैस और फ्लैश बैंग ग्रेनेड का इस्तेमाल करना पड़ा। बताया गया है कि अवैध श्रमिकों की तलाश में कार्यस्थलों पर छापे मारने के बाद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। रविवार को लॉस एंजिल्स के डाउनटाउन में दूसरी बार झड़प हुई।

कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसन ने कहा है कि ट्रंप ने नेशनल गार्ड के जवानों को जानबूझकर भेजकर स्थिति को और बिगाड़ दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने बिना उनकी सहमति से ऐसा कर संघीय शक्तियों का दुरुपयोग किया है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि आव्रजन अधिकारियों के रास्ते में आने वाले किसी भी प्रदर्शन को संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ विद्रोह माना जाएगा।

फोटोः हि.स.

उल्लेखनीय है कि लॉस एंजिल्स के दक्षिण में एक छोटे से शहर पैरामाउंट से शुरू यह विरोध प्रदर्शन अन्य जगहों पर फैल गया। पैरामाउंट में बड़ी संख्या में लैटिनो आबादी है। ट्रंप की आव्रजन कार्रवाई अगले साल के विश्व कप पर एक बाधा के रूप में आकार ले रही है। कुछ फुटबॉल प्रशंसक इससे भयभीत हैं।

लॉस एंजिल्स टाइम्स अखबार के अनुसार, रविवार को कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड के सैनिक लॉस एंजिल्स पहुंचे। उन्होंने आव्रजन एजेंटों की मदद करते हुए प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की कोशिश की। ट्रंप के लगभग 2,000 नेशनल गार्ड सैनिकों को भेजने से राज्य और स्थानीय अधिकारी भी भड़क गए हैं।

अल जजीरा की खबर के अनुसार, ट्रंप के सख्त कदम के बाद सुरक्षा बलों ने लॉस एंजिल्स के डाउनटाउन में आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां दागीं। एडवर्ड आर रॉयबल फेडरल बिल्डिंग, मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर और 101 फ्रीवे के पास तीसरे दिन भी झड़पें हुई हैं। इस बीच व्हाइट हाउस ने नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात करने के आदेश को रद्द करने की कैलिफोर्निया के गवर्नर की अपील को खारिज कर दिया है।

बीबीसी के अनुसार, लॉस एंजिल्स में फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। आव्रजन छापों के खिलाफ प्रदर्शनकारियों की तीसरे दिन भी कानून प्रवर्तन अधिकारियों के झड़पें हुई हैं। नेशनल गार्ड के सैनिकों ने कई जगह आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों ने शहर के प्रमुख 101 फ्रीवे को अवरुद्ध कर दिया। यहां नेशनल गार्ड के सैनिकों की जमकर झड़प हुई। लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने लॉस एंजिल्स के डाउनटाउन में अनके स्वचालित वाहनों को फूंक दिया। पुलिस के घोड़ों को हमला निशाना बनाया गया।

दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भरता से जोड़ रही योगी सरकार

दुकान निर्माण, संचालन योजना के तहत 1046 दिव्यांगों को मिला रोजगार

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)

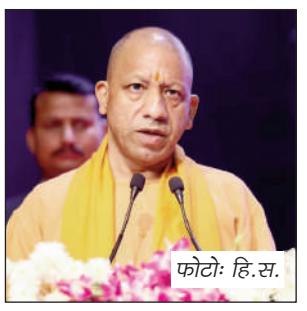

लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रभावशाली पहल की है। इसी क्रम में संचालित ₹दुकान निर्माण/संचालन योजना₹ ने प्रदेश के हजारों दिव्यांग नागरिकों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि योगी सरकार की योजना का मुख्य उद्देश्य है दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन जीने में समर्थ बनाना। योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 20,000 रुपये तक की धनराशि दुकान निर्माण अथवा संचालन के लिए दी जा रही है, जिसमें 15000 रुपये ऋण व 5000 रुपये अनुदान और दुकान संचालन के लिए 10,000 रुपये की राशि 75 प्रतिशत ऋण और 25 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है। योगी सरकार की यह व्यवस्था न केवल लाभार्थियों के लिए वित्तीय संबल बन रही है, बल्कि उन्हें अपने व्यवसाय की शुरूआत करने का आत्मविश्वास भी दे रही है। कई दिव्यांगजन जो पहले केवल सहायता के मोहताज थे, अब अपने दम पर व्यवसाय चला रहे हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन चुके हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार ने इस योजना के लिए 1.06 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया था। योजना का क्रियान्वयन प्रभावी, पारदर्शी और उद्देश्यपरक रहा है। इस राशि में से 1.05 करोड़ रुपये खर्च से कुल 1046 लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। इस योजना का सबसे बड़ा प्रभाव यह रहा है कि इससे दिव्यांगजनों में आत्मसम्मान की भावना जगी है। अब वे अपने परिवार का पालन-पोषण करने में सक्षम हो रहे हैं और समाज में सम्मान के साथ जी रहे हैं। चाय की दुकान, मोबाइल रिपेयरिंग, स्टेशनरी, जनरल स्टोर जैसी विभिन्न दुकानों के माध्यम से इन लाभार्थियों ने न केवल रोजगार पाया, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनने का कार्य किया।

'कोई पीछे न छूटे' की भावना से लगातार कार्य कर रही योगी सरकार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार इस बात पर जोर देती रही है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र को आत्मसात करते हुए यह योजना दिव्यांगजनों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है। योगी सरकार का मानना है कि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक स्थिति है, जिसे सही दिशा और सहायता के माध्यम से सशक्त बनाया जा सकता है। 'दुकान निर्माण/संचालन योजना' ने दिव्यांगजनों को केवल आर्थिक सहायता नहीं दी, बल्कि उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने में भी मदद की है।

चीन ने ताइवान में सैन्य घेरा बढ़ाया, सात विमान, आठ नौसैनिक जहाज भेजे

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)

ताइपे, (ताइवान)

ताइवान और चीन के बीच सैन्य टकराव बढ़ता ही जा रहा है। चीन लगातार ताइवान की घेराबंदी कर रहा है। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय (एमएनडी) ने कहा है कि आज सुबह छह बजे (स्थानीय समयानुसार) तक देश की क्षेत्रीय जल सीमा के पास चीन के सात विमानों और आठ नौसैनिक जहाजों को ट्रैक किया गया। चीन के सात में से पांच विमानों ने मध्य रेखा को पार कर ताइवान के दक्षिण-पश्चिमी और पूर्वी एडीआईजेड में प्रवेश किया। एमएनडी ने एक्स पोस्ट में कहा कि ताइवान के आसपास संचालित पीएलए विमानों और आठ पीएलएएन जहाजों की सात उड़ानें आज सुबह 6 बजे (यूटीसी+8) तक देखी गईं। सात में से पांच उड़ानें ताइवान के दक्षिण-पश्चिमी और पूर्वी एडीआईजेड में प्रवेश कर गईं। ताइवान की सेना ने इस पर जवाबी प्रतिक्रिया दी। एमएनडी ने एक अन्य एक्स पोस्ट में कहा कि रविवार को भी चीन के विमानों की 11 उड़ानें, सात चीनी नौसैनिक जहाजों को क्षेत्रीय जल सीमा के पास ट्रैक किया गया। 11 में से 6 उड़ानें ताइवान के दक्षिण-पश्चिमी एडीआईजेड में प्रवेश कर गईं। ताइवान की सेना ने निगरानी की और तदनुसार प्रतिक्रिया दी।

ममता बनर्जी ने बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उत्तर बंगाल के एक कॉलेज का नाम इस महान क्रांतिकारी के नाम पर रखा है। साथ ही उनके जन्मदिन के मौके पर पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है। एक्स (पूर्व ट्विटर) पर ममता बनर्जी ने लिखा, 'जॉय जोहार। बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। हमें गर्व है कि उत्तर बंगाल के एक कॉलेज का नाम हमने इस वीर विद्रोही के नाम पर रखा है। इसके अलावा, उनके जन्मदिन को राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर हम उन्हें सम्मानित करते हैं। मैं एक बार फिर इस महान आदिवासी नायक को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं।' बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून, 1900 को रांची की पुरानी सेंट्रल जेल में हुई थी। उनका जन्म 15 नवंबर, 1875 को हुआ था। उनके जन्मदिन को पूरे देश में 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

अमेरिका से निर्वासित किए 37 नेपाली नागरिकों को चार्टर्ड विमान से काठमांडू लाया गया

एजेंसी (हि.स.)

काठमांडू

अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे 37 नेपाली नागरिकों को रविवार की देर शाम को एक विशेष चार्टर्ड विमान से निर्वासित किए जाने के बाद त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाया गया। काठमांडू पहुंचने पर निर्वासितों को तुरंत नेपाली आप्रवासन अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों द्वारा पूछताछ करके उन्हें अपने गंतव्य तक जाने दिया गया।

फोटोः हि.स.

नेपाल के आप्रवासन विभाग के अनुसार, निर्वासित लोगों में वे व्यक्ति शामिल हैं जो या तो अपने वीजा से अधिक समय तक रहे थे, या अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश कर चुके थे, या अपनी आप्रवासन स्थिति को नियमित करने में विफल रहे थे।

निर्वासित लोगों से पूछताछ के बाद आप्रवासन अधिकारियों ने बताया कि कुछ को कथित तौर पर त्वरित निष्कासन प्रक्रियाओं के तहत भी हिरासत में लिया गया था। यह एक ऐसी नीति है जो अमेरिकी अधिकारियों को पूर्ण अदालत की सुनवाई के बिना भी अनिर्दिष्ट प्रवासियों को निर्वासित करने की अनुमति देती है यदि वे दो साल से कम समय से अवैध रूप से देश में हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद नए सिरे से आव्रजन प्रवर्तन नीतियों के तहत अन्य देशों की तरह ही नेपाली नागरिकों का निर्वासन बढ़ गया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 2025 में अब तक 150 नेपालियों को अमेरिका से निर्वासित किया गया है जो पूरे 2024 में निर्वासित की गई संख्या से दोगुने से अधिक है। यहां तक कि जिन लोगों ने पहले अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) के तहत शरण लिया था उन्हें भी निर्वासित होने के लिए कह दिया गया है।

ट्रम्प प्रशासन ने अभी कुछ दिन पहले ही औपचारिक रूप से नेपाली नागरिकों के लिए टीपीएस को समाप्त कर दिया - एक ऐसी नीति जिसने एक बार 2015 के भूकंप के बाद अमेरिका में रहने वाले लगभग 7,000 नेपालियों को निर्वासित होना पड़ेगा।

संक्षिप्त-समाचार

बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हामिद थाईलैंड से इलाज करवाकर स्वदेश लौटे

ढाका। बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हामिद थाईलैंड से इलाज करवाकर स्वदेश लौट आए। वह सोमवार आधीरात लगभग 1:30 बजे थाई एयरवेज की उड़ान (टीजी 339) से ढाका पहुंचे। औपचारिक प्रक्रिया को पूरा करने के बाद वह लगभग 2:45 बजे हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से घर के लिए रवाना हुए। ढाका ट्रिब्यून अखबार की खबर के अनुसार, हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्यकारी निदेशक ग्रुप कैप्टन रागीब समद ने अब्दुल हामिद के स्वदेश लौटने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि अब्दुल हमीद नियमित यात्री के रूप में लौटे और उन्होंने कोई विशेष प्रोटोकॉल नहीं मांगा। पिछले साल पांच अगस्त को बड़े पैमाने पर छात्र और सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना और उनकी पार्टी के पतन के बाद कई अवामी लीग के नेता देश छोड़कर भाग गए थे। हालांकि, अब्दुल हामिद बांग्लादेश में ही रहे। हामिद नौ महीने बाद चिकित्सा कारणों से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक चले गए। अब्दुल हामिद कथित तौर पर हत्या के एक मामले का सामना कर रहे हैं। यह मामला 14 जनवरी को किशोरगंज सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। इसी मामले में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, शेख रेहाना, सजीब वाजेद जॉय, साइमा वाजेद पुतुल और ओबैदुल कादर का भी नाम है। हामिद ने अवामी लीग के शासन के दौरान 2013 से 2023 तक लगातार दो कार्यकाल के लिए बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।

राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर: श्रीगंगानगर सबसे गर्म शहर, नौ शहरों में यलो अलर्ट

जयपुर। राजस्थान में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राज्य के उत्तर-पश्चिमी जिलों में भीषण लू का प्रकोप जारी है। रविवार को श्रीगंगानगर देश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस मापा गया। सोमवार को भी गर्मी से राहत के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग ने बीकानेर और श्रीगंगानगर के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि नौ शहरों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। टोंक और आसपास के क्षेत्रों में सोमवार सुबह हल्के बादल छाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पाई। धूप के साथ उमस भी बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को प्रदेश के आठ से ज्यादा शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। बीकानेर 46 डिग्री, चूरू 45.6 डिग्री, फलोदी 45.4, जैसलमेर 45.2, बाड़मेर 45.9, कोटा 45 डिग्री, पिलानी और वनस्थली (टोंक) 44.2 डिग्री, जयपुर 43.5, भीलवाड़ा, अलवर और जोधपुर में 43.4 डिग्री सेल्सियस मापा गया। राजधानी जयपुर में तापमान 1.7 डिग्री की बढ़त के साथ 43.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सोमवार को भी शहरवासियों को सुबह से ही गर्म हवाओं और धूप ने परेशान कर रखा है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, प्रदेश में अगले दो दिन तक लू से राहत की संभावना नहीं है। खासकर श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, बाड़मेर और फलोदी जैसे शहरों में गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में श्रीगंगानगर और बीकानेर व यलो अलर्ट वाले जिलों में चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, पिलानी, टोंक (वनस्थली), भीलवाड़ा, अलवर, जयपुर शामिल है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि लोग दोपहर 12 से तीन बजे तक घर से बाहर निकलने से बचें, अधिक पानी पिएं और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाएं।

बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के कमांडर एके खांडकर की पत्नी फरीदा नहीं रहीं

ढाका। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ, एयर ऑपरेशन किलो फ्लाइट के कमांडर और पूर्व चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर वाइस मार्शल एके खांडकर की पत्नी फरीदा खांडकर का निधन हो गया है। उन्होंने रविवार को ढाका के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में 82 साल की आयु में अंतिम सांस ली। उनके परिवार में दो बेटे और एक बेटी हैं। ढाका ट्रिब्यून अखबार की खबर के अनुसार, बांग्लादेश के इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने कहा कि वायुसेना प्रमुख ने फरीदा खांडकर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के साथ शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। खबर में कहा गया है कि आज ढाका में बीएएफ शाहीन मस्जिद में अस्र की नमाज के बाद उनकी नमाज-ए-जनाजा होगी। इसके बाद बीएएफ शाहीन कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया जाएगा।

स्टेट बैंक ने सरकार को दिया 8076.84 करोड़ रुपये का लाभांश

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने सोमवार को 8,076.84 करोड़ रुपये के लाभांश का चेक सौंपा। इस अवसर पर वित्त सचिव अजय सेठ और वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) सचिव एम. नागराजू भी मौजूद रहे। वित्त मंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सी. श्रीनिवास सेट्टी से केंद्रीय वित्त मंत्री को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 8,076.84 करोड़ रुपये का लाभांश चेक प्राप्त हुआ। ये राशि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के 6,959 करोड़ रुपये के लाभांश से अधिक है, जो एसबीआई के उल्लेखनीय वृद्धि दशार्ता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय स्टेट बैंक एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक के साथ वित्तीय सेवा निकाय है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। बैंक की परिसंपत्तियों के हिसाब से 23 फीसदी बाजार हिस्सेदारी है, जबकि कुल ऋण और जमा बाजार में इसकी हिस्सेदारी 25 फीसदी है। यह करीब 250,000 कर्मचारियों के साथ भारत का दसवां सबसे बड़ा नियोक्ता भी है।

पेटीएम ने लॉन्च की पर्सनलाइज्ड यूपीआई आईडी सुविधा, ऐसे करें इस्तेमाल

नई दिल्ली। ऑनलाइन भुगतान और वित्तीय सेवा वितरण कंपनी पेटीएम ने सोमवार को व्यक्तिगत यूपीआई आईडी लॉन्च किया है। ये सुविधा भुगतान गोपनीयता को बढ़ाएगी और मोबाइल नंबर के खुलासे को रोकेगी। पेटीएम की इस नई सर्विस के तहत अब उपभोक्ता अपनी पर्सनलाइज्ड यूपीआई आईडी बना सकते हैं। पेटीएम की इस नई सर्विस से यूजर्स अपने मोबाइल नंबर को प्राइवेट रख सकते हैं, जिससे उनकी प्राइवेसी बढ़ेगी। पेटीएम की नई पेशकश नई पर्सनलाइज्ड यूपीआई आईडी में आप नाम@ptyes और नाम@ptaxis जैसी UPI आईडी भी बना सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर बताए बिना पैसे भेज और प्राप्त कर सकते हैं।

इजराइल के नेता प्रधानमंत्री नेतन्याहू से निराश, नेसेट को भंग करने की तैयारी

एजेंसी (हि.स.)

तेल अवीव

इजरायल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय लिबरल मूवमेंट (लिकुड) के शीर्ष नेता बेंजामिन नेतन्याहू पर संकट के बादल गहराने लगे हैं। दक्षिण पंथी लिकुड के नेता को बुधवार को नेसेट में विरोधी दलों से अब तक की सबसे तगड़ी चुनौती मिल सकते हैं। इन दलों ने नेसेट को भंग करने की तैयारी शुरू कर दी है।

इजराइल में एक सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है। इसे नेसेट यानी संसद कहा जाता है। नेसेट के सदस्यों का चुनाव देश के नागरिक करते हैं। यह सदस्य कानून बनाने, सरकारी कार्यों की निगरानी करने और अन्य महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेसेट ही राष्ट्रपति को चुनती है। नेसेट में 120 सदस्य होते हैं।

फोटोः हि.स.

द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के अनुसार लिकुड की विरोधी पार्टी नेशनल यूनिटी के चेयरमैन बेनी गैंट्ज ने अपनी पार्टी को प्लेनम एजेंडे से बुधवार तक अपने सभी कानून वापस लेने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि नेसेट को भंग करने वाले बिल के अलावा सभी बिल वापस ले लिए जाएं। विपक्षी पार्टी ने बयान में कहा कि इससे नेसेट को भंग करने का रास्ता आसान हो जाएगा।

नेसेट को भंग करने वाला बिल अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स पार्टियों के सरकार को गिराने की धमकियों के बीच आया है। अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स शास पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि वह बुधवार को नेसेट को भंग करने के पक्ष में मतदान करेंगे। कोल बेरमाह रेडियो स्टेशन के साथ साक्षात्कार में शास के प्रवक्ता अशर मदीना ने कहा, जैसा कि स्थिति है, हम बुधवार को नेसेट को भंग करने के पक्ष में मतदान करेंगे। हम प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से निराश हैं।

नेतन्याहू का सत्तारूढ़ गठबंधन इस समय दबाव में है। पिछले हफ्ते से अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स पार्टियों यूनाइटेड टोरा यहूदी धर्म और शास ने येशिवा छात्रों को सैन्य सेवा से छूट देने वाला विधेयक पारित न करने पर गठबंधन छोड़ने और नेसेट को भंग करने की धमकी दे रही हैं।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति को आतंकवाद से नहीं, भारत के हिंदुत्व से नजर आ रहा क्षेत्रीय शांति को खतरा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व 'इस्लाम के पाक त्योहारों' पर भी झूठ बोलने से नहीं डरता। बकरीद त्योहार के तीसरे दिन सोमवार को राष्ट्रपति भवन में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के नेताओं और कार्यकताओं को शुभकामनाएं देते समय आतंकवाद को नहीं, बल्कि भारत के हिन्दुत्व को क्षेत्रीय शांति के खतरा बताया गया। दुनिया न्यूज की खबर के अनुसार राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस मौके पर कहा कि भारत का हिंदुत्व उग्रवाद एजेंडा क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है। भारत में मुसलमानों और ईसाइयों को भेदभाव व उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। हिंदुत्व उग्रवाद की विचारधारा पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बन रही है। जरदारी ने इस मौके पर आतंकवाद का जिक्र तक नहीं किया। वह भारत की आलोचना के बाद सीधे देश की अर्थव्यवस्था की बात करने लगे। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने की जरूरत है। इसे आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। कृषि मुल्क की अर्थव्यवस्था की नींव है।

ठाणे में चलती लोकल ट्रेन से गिरकर 6 यात्रियों की मौत, सात घायल

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)

मुंबई

ठाणे जिले में कोपर और दिवा स्टेशनों के बीच सोमवार को सुबह लोकल ट्रेन से गिरकर छह यात्रियों की मौत हो गई है। इस हादसे में सात यात्री घायल हो गए हैं, इन सभी को कलवा स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नीला स्वप्रिल ने बताया कि आज सुबह करीब साढ़े बजे आमने-सामने से विपरीत दिशा में जा रही दो लोकल ट्रेनों के फुटबोर्ड पर बैठे यात्री आपस में टकरा कर रेलवे पटरी के पास गिर गए। इस घटना में ८ लोगों को कोपर और दिवा के बीच रेलवे पटरी से उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि गार्ड ने पांच घायल यात्रियों को जीआरपी को सौंपा। इन सभी का इलाज कलवा सरकारी अस्पताल में हो रहा है, लेकिन मृतकों की जानकारी अस्पताल सूत्रों ने अभी तक नहीं दी है।

मुंब्रा के स्टेशन मास्टर ने पत्रकारों को बताया कि रेलवे पटरी में गिरने तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि पांच लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार इस घटना में खबर लिखे जाने तक छह लोगों की मौत हो गई है और सात लोगों का इलाज जारी है।

दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज एमएससी इरिना विझिनजाम बंदरगाह पर पहुंचा

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज एमएससी इरिना सोमवार को केरल के तिरुवनंतपुरम में विझिनजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह पर सुबह आठ बजे पहुंचा। कंटेरन जहाज के यहां पहुंचने पर उसका स्वागत पारंपरिक जल सलामी के साथ किया गया।

ये जहाज मंगलवार तक यहां रहेगा। दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज एमएससी इरिना ने विझिनजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह पर ऐतिहासिक शुरूआत की। दक्षिण एशियाई बंदरगाह की अपनी पहली यात्रा पर आया ये जहाज सुबह 8 बजे बंदरगाह पर पहुंचा, जिसने अल्ट्रा-लार्ज कंटेनर जहाजों (यूएलसीवी) को संभालने में विझिनजाम की क्षमताओं को उजागर किया। एमएससी इरिना, जिसे टीईयू (बीस फुट समतुल्य इकाई) क्षमता के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज बताया जा रहा है, जो मंगलवार तक बंदरगाह पर खड़ा रहेगा। विझिनजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह को अडाणी समूह ने बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 मई को इसका उद्घाटन किया। दुनिया के सबसे बड़े जहाज का आगमन नए बंदरगाह के लिए मील का पत्थर है। एमएससी इरिना जहाज की क्षमता 24,346 टीईयू की है, जो इसे वैश्विक शिपिंग में एक मजबूत खिलाड़ी बनाती है। 399.9 मीटर की लंबाई और 61.3 मीटर की चौड़ाई के साथ यह जहाज फीफा द्वारा नामित एक मानक फुटबॉल मैदान से लगभग चार गुना लंबा है। इस को मार्च, 2023 में लॉन्च किया गया था, जो उसी वर्ष अप्रैल में अपनी पहली यात्रा पर निकला था। लाइबेरियाई झंडे के नीचे चलने वाला यह जहाज 26 स्तरों तक ऊंचे कंटेनरों को ढेर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कंटेनर स्टैकिंग में बेजोड़ क्षमता प्रदान करता है।

हनुमत धाम के भूमि पूजन कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए मुख्यमंत्री

सनातन संस्कृति के केंद्र के रूप में पहचान बना रहा है भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

कहा- कैंची धाम वाले नीम करोली महाराज के हनुमत धाम निर्माण से भोपाल की आभा और कीर्ति बढ़ेगी

एजेंसी (हि.स.)

भोपाल

फोटोः हि.स.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भोपाल सनातन संस्कृति के केंद्र के रूप में पहचान बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है। कैंची धाम वाले नीम करोली महाराज के हनुमत धाम के निर्माण से भोपाल की आभा और कीर्ति बढ़ेगी। भोपाल में राजा भोज के नाम से भोज द्वार बनाने का संकल्प लिया था, हनुमत धाम निर्माण भी इसी दिशा में एक कदम है। सम्राट विक्रमादित्य सहित भारतीय संस्कृति से जुड़े सभी गौरवशाली पक्षों को यहां प्रदर्शित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को कैंची धाम वाले नीब करोली महाराज के रतनपुर भोपाल में बन रहे हनुमत धाम के भूमि पूजन कार्यक्रम को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर प्रकाशित स्मारिका कैंची धाम वाले नीब करोली महाराज-बाबा का हनुमत धाम का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल में बाबा का धाम बनाने का राम राज बाबा नीब करौरी चैरिटेबल ट्रस्ट का संकल्प स्वागत योग्य है। बाबा से जुड़े कार्यक्रम में सम्मिलित होना सौभाग्य का विषय है। धाम निर्माण का संकल्प एक अध्यात्मिक युग के सूत्रपात जैसा है। उन्होंने कहा कि कैंची धाम की महिमा देश-विदेश में अनुभव की जा रही है। वैश्विक स्तर पर उनके अनुभवों और संदेशों से लोग प्रेरणा ले रहे हैं। भोपाल का यह धाम सम्पूर्ण प्रदेश और आस-पास के राज्यों के लिए बाबा के आशीर्वाद का केन्द्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने धाम के लिए डॉ. बृजेश श्रीवास्तव द्वारा भूमि समर्पित करने के लिए उनकी सराहना करते हुए भूमि दान को अनुकरणीय पहल बताया।

कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित खेल एवं युवा कल्याण तथा सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग तथा सांसद वीडी शर्मा ने भी अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में हितानंद शर्मा, आशीष अग्रवाल, डॉ. बृजेश श्रीवास्तव, नितेन्द्र शर्मा, अनिता अग्निहोत्री तथा बाबा नीम करौरी की पौत्र-वधु शैलजा शर्मा उपस्थित थीं। रतनपुर स्थित कार्यक्रम स्थल पर सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा तथा भगवानदास सबनानी, बाबा नीब करौरी के पौत्र डॉ. धनंजय शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार राकेश अग्निहोत्री सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

पीवीएल 4 नीलामी: जेरोम विनीत, शमीमुद्दीन और विनीत कुमार सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बने

कुल 789 खिलाड़ियों की बोली, 10 फ्रेंचाइजियों ने किए 6 करोड़ से अधिक खर्च

एजेंसी (हि.स.)
कालीकट

प्राइम वॉलीबॉल लीग (पीवीएल) सीजन 4 की नीलामी में रविवार को जेरोम विनीत सी, शमीमुद्दीन और विनीत कुमार ने सबसे अधिक बोली हासिल कर सुर्खियां बटोरीं। इन तीनों खिलाड़ियों को प्लेटिनम कैटेगरी में रु 22.5 लाख की कीमत पर खरीदा गया। जेरोम विनीत को चेन्नई ब्लिट्ज ने अपनी टीम में शामिल किया, वहीं शमीमुद्दीन को कालीकट हीरोज और विनीत कुमार को कोच्चि ब्लू स्पाइकर्स ने अपनी टीम में जोड़ा।

इस बार नीलामी में कुल 789 खिलाड़ी शामिल हुए, जिन पर 10 फ्रेंचाइजियों ने बोली लगाई। कुल रु 6 करोड़ 8 लाख 50 हजार की राशि खर्च की गई। हर फ्रेंचाइजी को अपने पुराने खिलाड़ियों को रिटेन करने या उन्हें ऑक्शन पूल में छोड़ने का विकल्प मिला था। विदेशी खिलाड़ियों का चयन ड्राफ्ट सिस्टम से किया गया।

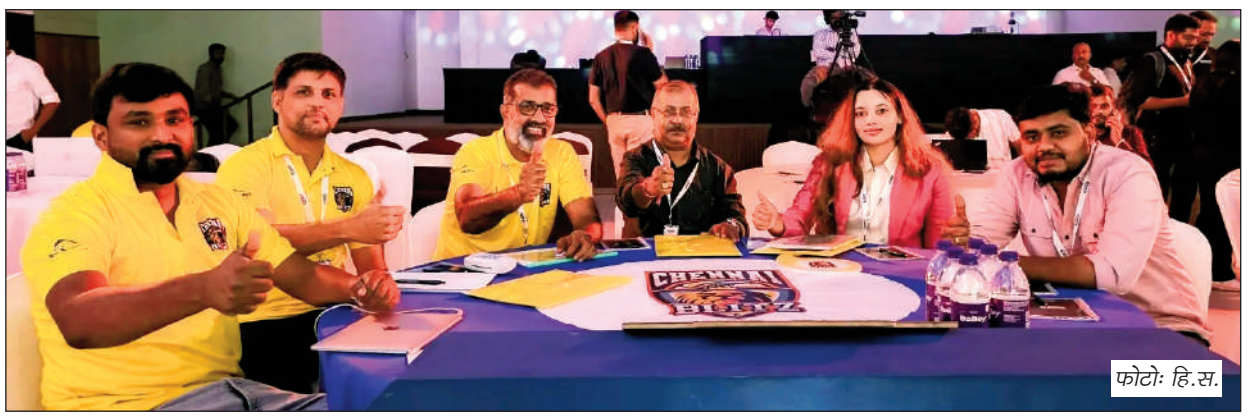
फोटोः हि.स.

चेन्नई ब्लिट्ज की खरीदारी

जेरोम विनीत के अलावा चेन्नई ब्लिट्ज ने एम. अश्विन राज, आदित्य राणा और समीर चौधरी को रु 8 लाख में, नांजिल सूर्या को रु 5.75 लाख, टी. श्रीकांत को रु 6.5 लाख, तरुण गौड़ा के को रु 4.25 लाख, कैला विष्णु वर्धन बाबू और नमिथ एमएन को रु 3 लाख में खरीदा।

कोच्चि ब्लू स्पाइकर्स ने भी दिखाई आक्रामकता

विनीत कुमार के साथ कोच्चि ब्लू स्पाइकर्स ने जसजोध सिंह को रु 14.75 लाख, अमलके थॉमस को रु 6.5 लाख, जानशाद यू को रु 4.25 लाख, और अयुष पांडे, निर्मल जॉर्ज, सचिन के, हेमंत पी और एलन अशोक वीएल को रु 3 लाख में खरीदा।

कालीकट हीरोज की संतुलित टीम

शमीमुद्दीन के अलावा कालीकट हीरोज ने संतोश एस को रु 11.5 लाख, मोहनुक्रापांडियन को रु 8 लाख, अब्दुल रहीम और मुकेश कुमार को रु 4 लाख तथा हारिस, किरणराज थेवलिल और उसामा रहमत को रु 3 लाख में टीम में शामिल किया।

अहमदाबाद डिफेंडर्स का मजबूत दांव

अहमदाबाद डिफेंडर्स ने शॉन टी जॉन को रु 11.5 लाख, अंगमुथु को रु 11 लाख, अखिन जीएस को रु 10.25 लाख में खरीदा। अर्शक सिनान को रु 8 लाख, पी. प्रभाकरण को रु 3.25 लाख, जबकि ध्रुविल पटेल, अभिनव बीएस और हर्ष चौधरी को रु 3 लाख में टीम का हिस्सा बनाया।

बेंगलुरु टॉरपीडोज ने देर से लेकिन बड़ा दांव खेला

बेंगलुरु टॉरपीडोज ने जिश्नू पीवी को रु 14 लाख में खरीदा। जोएल बेंजामिन जे रु 6.5 लाख में टीम से जुड़े, वहीं रोहित कुमार और इबिन जोस को रु 5 लाख में, हिमांशु त्यागी को रु 4.25 लाख में और संदीप को रु 3 लाख में टीम में शामिल किया गया। नितिन मिन्हास को रु 4.2 लाख में खरीदा गया।

दिल्ली तूफान ने कई बड़े नामों पर दांव लगाया

दिल्ली तूफान ने मुहम्मद जसीम को रु 11 लाख, आयुष को रु 9 लाख, मन्नत चौधरी को रु 6.5 लाख, जॉर्ज एंटनी को रु 5 लाख और अभिषेक राजीव, अविनाश व रिजास केआर को रु 3 लाख में टीम में शामिल किया।

हैदराबाद ब्लैक हॉक की बड़ी खरीदारी

हैदराबाद ब्लैक हॉक ने शिखर सिंह को रु 16 लाख, अमन कुमार को रु 11.5 लाख, दीपु वेंगुपाल को रु 5.75 लाख, प्रीत करण को रु 4.75 लाख, राजनीश सिंह, अथुल और दिग्विजय सिंह को रु 3 लाख में खरीदा।

कोलकाता थंडरबोल्ट्स की ठोस टीम

कोलकाता ने पंकज शर्मा को रु 6 लाख, स्रजन शेट्टी को रु 5 लाख, जितिन एन को रु 5.75 लाख, सूर्यांश तोमर को रु 4 लाख, लालसुजन एमवी को रु 6.25 लाख, मुहम्मद इकबाल को रु 7 लाख, अमित चौकर को रु 5 लाख और मुहम्मद फवाज एम को रु 3 लाख में टीम से जोड़ा।

मुंबई मीटियर्स का संतुलित चयन

मुंबई ने लाड ओमवसंत और कार्तिक ए को रु 8 लाख, सोनू, निखिल और विपुल कुमार को रु 5 लाख, निखिल चौधरी को रु 4 लाख और अभिनव सालार व योगेश कुमार को रु 3 लाख में खरीदा।

गोवा गार्जियंस की रणनीति

गोवा ने प्रिंस और रमणाथन आर को रु 8 लाख, विक्रम और दुश्यंत सिंह को रु 4 लाख, रोहित यादव को रु 3.5 लाख और जैरी डेनियल को रु 3 लाख में खरीदा।

पीवीएल सीजन 4 की नीलामी में खिलाड़ियों की मांग और टीमों की रणनीति ने एक बार फिर दिखा दिया कि भारत में वॉलीबॉल का क्रेज लगातार बढ़ रहा है।

मार्क मार्केज ने अरागोन ग्रां प्री जीतकर पूरा किया परफेक्ट वीकेंड, डुकाटी का पोडियम पर कब्जा

एजेंसी (हि.स.)
अल्कानीज (स्पेन)

डुकाटी के स्टार राइडर मार्क मार्केज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मोटरलैंड सर्किट पर उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने पोल पोजिशन से शुरूआत करते हुए अरागोन ग्रां प्री में शानदार जीत दर्ज की और चैंपियनशिप में अपनी बढ़त और मजबूत कर ली। इस जीत के साथ मार्क ने न केवल सीजन की सातवीं जीत हासिल की, बल्कि इस सर्किट पर रिकॉर्ड सातवीं बार जीतकर इतिहास भी रच दिया। उनके छोटे भाई एलेक्स मार्केज ने ग्रेसिनी रेसिंग के लिए दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि डुकाटी टीम के ही फ्रांसेस्को बगनाइया तीसरे स्थान पर रहे। इस तरह डुकाटी ने पोडियम पर पूरी तरह कब्जा जमाया।

मार्क मार्केज ने वीकेंड के हर सेशन – प्रैक्टिस, क्वालिफाइंग, वार्मअप और रेस – में टॉप पर रहकर 2015 जर्मन ग्रां प्री के बाद पहली बार किसी राइडर ने हर सेशन में बढ़त बनाई। उस समय भी ये कारनामा खुद मार्क ने ही किया था। उन्होंने कहा, 'यह वीकेंड

फोटोः हि.स.

शानदार रहा। हर सेशन में लीड करना, पूरा फोकस बनाए रखना जरूरी था। एलेक्स और पेको (बगनाइया) की रेस पेस तेज थी, लेकिन मैं गैप कंट्रोल करता रहा। भाई के साथ जीत सेलिब्रेट करना बहुत खास था।'

रेस से पहले दोनों मार्केज भाइयों के बीच सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर मजेदार बहस चल रही थी कि उनकी मां किसे सपोर्ट करेंगी। रेस जीतने के बाद मार्क ने अपनी मां को डुकाटी की लाल शर्ट भेंट की, जिससे मजेदार लम्हा बन गया। रेस के बाद दोनों भाई घरेलू दर्शकों के सामने हाथ में हाथ डालकर डांस करते भी दिखे, जो उनके सम्मान में बनाए गए विशेष स्टैंड में मौजूद थे।

अल्कारेज ने सिनर को हराकर फ्रेंच ओपन जीता

पेरिस। दूसरे वरीय और गत विजेता कार्लोस अल्कारेज ने दो सेट गंवाने के बाद जोरदार वापसी करते हुए रविवार को यहां दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर को पांच सेट तक चले कड़े मुकाबले में हराकर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया। दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी स्पेन के अल्कारेज ने तीन मैच प्वाइंट बचाते हुए शीर्ष वरीय सिनर को पांच घंटे 29 मिनट में 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6 से हराकर इटली के खिलाड़ी के ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट में लगातार 20 जीत के अभियान पर विराम लगाया। सिनर ने पिछले साल अमेरिकी ओपन और इस साल ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीता था और उनकी नजरें पेरिस में ग्रैंडस्लैम जीत की हैट्रिक पूरी करने पर थी। दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी अल्कारेज का यह पांचवां ग्रैंडस्लैम खिताब है जबकि सिनर के नाम तीन ग्रैंडस्लैम खिताब दर्ज हैं। अल्कारेज ने अब तक कोई ग्रैंडस्लैम फाइनल नहीं गंवाया है जबकि सिनर को पहली बार ग्रैंडस्लैम के खिताबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा।

पुर्तगाल ने पेनल्टी शूटआउट में स्पेन को हराकर दूसरी बार जीता नेशंस लीग का खिताब

एजेंसी (हि.स.)
म्यूनिख

क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगुवाई में पुर्तगाल ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए यूएफा नेशंस लीग का खिताब अपने नाम कर लिया। रविवार को खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में पुर्तगाल ने स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में 5-3 से हराया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थीं। मुकाबले की शुरूआत स्पेन के पक्ष में रही, जब 21वें मिनट में मार्टिन जुबिमेंडी ने अपना दूसरा अंतरराष्ट्रीय गोल करते हुए टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। लेकिन जल्द ही पुर्तगाल ने वापसी की और नूनो मेंडेस ने रोनाल्डो की मदद से शानदार गोल करते हुए स्कोर 1-1 कर दिया। स्पेन ने पहले हाफ के अंत तक फिर से बढ़त बनाई। मिडफील्डर पेड्री के बेहतरीन पास पर मिकेल ओयारजाबाल ने गोल कर टीम को 2-1 की बढ़त दिला दी। हालांकि, दूसरे हाफ में रोनाल्डो ने एक बार फिर मौके

फोटोः हि.स.

का फायदा उठाया और 138वां अंतरराष्ट्रीय गोल दागते हुए पुर्तगाल को बराबरी दिला दी।

मैच के अंतिम क्षणों में रोनाल्डो चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए। अतिरिक्त समय में भी दोनों टीमों के बीच कोई फर्क नहीं पड़ा और मुकाबला पेनल्टी शूटआउट तक पहुंचा। यहां स्पेन के अल्वारो मोराटा चूक गए, जबकि पुर्तगाल ने अपने सभी पांच पेनल्टी गोल में बदले। आखिरी किक रूबेन नेवेस ने लगाई और पुर्तगाल को दूसरी बार नेशंस लीग चैंपियन बना दिया। जीत के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने आंसू नहीं रोक सके। यह संभवतः उनका आखिरी बड़ा टूर्नामेंट हो सकता है और टीम को ट्रॉफी दिलाकर वह भावुक हो उठे। 40 साल की उम्र में भी उनका जज्बा और प्रदर्शन प्रशंसकों के लिए प्रेरणादायक रहा।

स्पेन ने सेमीफाइनल में फ्रांस को 5-4 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था और मार्च 2023 से वह अपराजित रहा था। यूरो 2024 का खिताब जीतने के बाद यह उनका लगातार दूसरा बड़ा फाइनल था, लेकिन इस बार रोनाल्डो और पुर्तगाल के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को चार विकेट से हराकर टी20 श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई

एजेंसी (हि.स.)
ब्रिस्टल (इंग्लैंड)

इंग्लैंड ने तीन मैचों की श्रृंखला के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में वेस्टइंडीज को नौ गेंद शेष रहते चार विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। टीम ने इससे पहले तीन मैचों की वनडे श्रृंखला में भी सूपड़ा साफ किया था जिससे नये कप्तान हैरी ब्रुक को 11 दिनों के अंदर दूसरी श्रृंखला में जीत दर्ज की। जोस बटलर के बाद टीम की कमान संभालने वाले ब्रूक की यह पांच मैचों में पांचवीं जीत है।

वेस्टइंडीज ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर छह विकेट पर 196 रन बनाये। इंग्लैंड ने 18.3 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 199 रन बनाकर मैच और श्रृंखला जीत ली। इंग्लैंड ने नौ गेंद शेष रहते जीत दर्ज की लेकिन उसके लिए वेस्टइंडीज के लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं था। जरूरी रनरेट एक समय 11 रन प्रति ओवर से अधिक हो गया था।

फोटोः हि.स.

टीम हालांकि शीर्ष क्रम में छह में से पांच बल्लेबाजों के शानदार प्रयास से जीत दर्ज करने में सफल रही।

जैकब बेथेल (10 गेंद में 26 रन) और टॉम बैंटन (11 गेंद में नाबाद 30) ने पांचवें विकेट के लिए सिर्फ 21 गेंदों पर 56 रन की साझेदारी कर वेस्टइंडीज की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। श्रृंखला के शुरूआती मैच में 96 रन बनाने वाले बटलर ने 36 गेंदों पर 47 रन बनाकर एक बार फिर टीम के शीर्ष स्कोरर रहे। वेस्टइंडीज ने इससे पहले आखिरी दो ओवर में 47 रन बटोर कर प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया।

यात्रा के दौरान पैसा बचाने में मदद करेंगे ये कुछ टिप्स

क्या आप भी उन लोगों में से हैं, जिनका बजट छोटी-मोटी ट्रिप में ही बिगड़ जाता है। जाहिर है, जब 2-3 दिनों की ट्रिप में ही जेब खाली होने लगे, तो घर आने के बाद इस फिजूलखर्ची का पछतावा जरूर होता है और फिर कई दिनों तक घूमने-फिरने का मन भी नहीं करता है। ऐसे में, यहां हम आपके लिए कुछ स्पेशल टिप्स लेकर आए हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए ट्रिप प्लान करने पर न सिर्फ आप मजे से अपने सफर को एन्जॉय कर पाएंगे, बल्कि पैसों की बचत में भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी।

पहले से करें प्लानिंग

ट्रैवल से पहले ही सब कुछ प्लान कर लें। जी हां, घर पर ही सोच लें कि कहां-कहां जाना है, कहां रुकना है और क्या देखना है। सब कुछ पहले से तय कर लें, क्योंकि लास्ट मिनट की बुकिंग अक्सर महंगी होती है। इसलिए, जितनी जल्दी आप बुकिंग करेंगे, उतनी ही ज्यादा बचत हो पाएगी।

ऑफ-सीजन में बनाएं प्लान

ऑफ-सीजन में ट्रिप प्लान करना अक्सर कम खचीर्ला होता है, क्योंकि इन दिनों टूरिस्ट कम होते हैं। ऐसे में, होटल और फ्लाइट दोनों की कीमतें कम देखने को मिलती हैं। इस समय का एक और बड़ा फायदा यह भी है कि भीड़ कम होने से आप जगहों का अच्छे से लुत्फ उठा पाते हैं।

बजट फ्रेंडली अकोमोडेशन चुनें

बड़े और महंगे होटलों की बजाय हॉस्टल, गेस्ट हाउस या धर्मशाला जैसे ऑप्शन चुनें। ये न सिर्फ सस्ते होते हैं, बल्कि आपको स्थानीय संस्कृति के करीब आने का मौका भी देते हैं, जो कि किसी भी जगह कि ट्रिप को एन्जॉय करना का बेस्ट तरीका होता है।

लोकल फूड का उठाएं लुत्फ

रेस्तरां में खाने की बजाय लोकल ढाबों या स्ट्रीट फूड का मजा लें। यह न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ता है। साथ ही, यह आपको उस जगह के असली स्वाद से भी रूबरू कराता है।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट का करें यूज

टैक्सी या कैब पर ज्यादा खर्च करने से बचें। इसके बजाय आप लोकल बसों, ट्रेनों या मेट्रो का इस्तेमाल करें। ट्रांसपोर्ट के यह साधन किफायती होने के साथ-साथ आपको शहर को करीब से देखने का मौका भी देता है।

घूमने की जगहों पर रिसर्च करें

ऐसी जगहों को प्रायोरिटी दें जहां एंट्री फीस कम हो या बिल्कुल न हो। कई शहर ऐसे होते हैं जहां घूमने के लिए कई मुफ्त जगहें होती हैं, जैसे पार्क, मंदिर या ऐतिहासिक स्मारक।

स्नैक्स और पानी साथ रखें

ट्रैवल के दौरान हल्की-फुल्की भूख लगने पर बाहर से कुछ खरीदने के बजाय अपने साथ स्नैक्स और पानी रखें। इससे आप बेवजह के खर्च से बचेंगे और बाहर के खाने को लिमिट करके आपका डाइजेशन भी बेहतर रहेगा।

यादगार चीजों पर ऐसे करें खर्च

घूमने की याद के तौर पर आप लोकल मार्केट से छोटी-मोटी यादगार चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन बहुत महंगी चीजों पर पैसा बर्बाद करने से बचें। ध्यान रहे, यादें तस्वीरों और अनुभवों से बनती हैं, सिर्फ चीजों से नहीं।

गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के साथ इन जगहों को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाएं

जैसे ही बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं, बच्चे घूमने की जिद्द करने लगते हैं। क्या आप भी अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने जाने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हां, तो आप गर्मियों में भारत की इन बेहद खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करने का प्लान बना सकते हैं।

ऋषिकेश

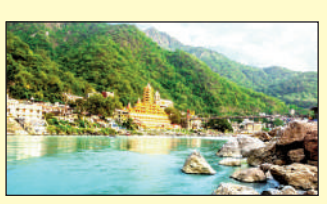

ऋषिकेश में आप अपने परिवार के साथ एक से बढ़कर एक जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऋषिकेश में आप नीलकंठ महादेव मंदिर, लक्ष्मण झूला, राम झूला, त्रिवेणी घाट और बीटल्स आश्रम के अलावा नीलगढ़ झरना, त्रिम्बकेश्वर मंदिर, भरत मंदिर, ऋषि कुंड, ऋषिकेश गंगा आरती और झिलमिल गुफा भी देख सकते हैं।

खज्जियार

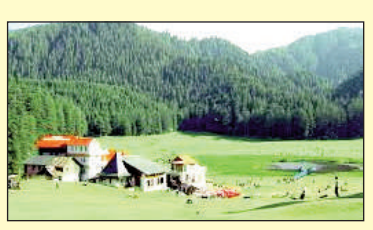

2-4 दिन में हिमाचल प्रदेश में स्थित खज्जियार को एक्सप्लोर किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खज्जियार नाग देवता को समर्पित खज्जी नागा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसी मंदिर के नाम से ही इस जगह का नाम पड़ा है।

दार्जिलिंग

दार्जिलिंग एक बेहद खूबसूरत जगह है जिसे परिवार के साथ एक्सप्लोर किया जा सकता है। दार्जिलिंग में घूमने के लिए कुछ प्रमुख जगहों में टाइगर हिल, घूम मठ, दार्जिलिंग टॉय ट्रेन, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट और हैप्पी वैली टी एस्टेट का नाम शामिल होता है।

मुन्नार

मुन्नार की खूबसूरती देश-विदेश से आए टूरिस्ट्स का दिल जीत लेती है। मुन्नार चाय के बागानों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। मुन्नार में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, कन्नन देवन टी म्यूजियम, मट्टुपेट्टी बांध, पोथामेडु व्यू पॉइंट, अनमुडी पीक और चिन्नार वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी को एक्सप्लोर किया जा सकता है।

मुख्य सचिव ने एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान के अंतर्गत सभी उपायुक्तों से ज्यादा से ज्यादा पेड लगाने की अपील की

एसडीएम ने जिले के सभी अधिकारियों को अगले सप्ताह से पेड लगाने का कार्य शुरू करने के दिए निर्देश

- मुहिम में वन मित्रों, नेहरू युवा केंद्र तथा अन्य विभागों को भी जोडा जाएः कटारिया

संवाददाता

पंचकूला

हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने योमवार को चंडीगढ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एक पेड माँ के नाम 2.0 अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों एवं वन्य अधिकारियों की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की और निर्देश दिए कि सभी जिलों में अधिक से अधिक पौधारोपण किया जाए। कटारिया ने मुख्य सचिव को अवगत करवाया कि जिला पंचकूला में पिछले साल 1 लाख 60 हजार पौधे सरकारी स्कूल, निजी स्कूल, खेल स्टेडियम व पंचायत की जमीन पर लगाए गए थे। उन्होने मुख्य सचिव को इस बार भी 1 लाख 60 हजार से ज्यादा पेड जिले में लगाने का आश्वासन दिया।

इसके उपरांत एसडीएम चंद्रकांत कटारिया ने सभी अधिकारियों की बैठक ली। उन्होने एक पेड माँ के नाम 2.0 के तहत सभी अधिकारियों से जिले में ज्यादा से ज्यादा पेड लगाने को लेकर चर्चा की। उन्होने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन विभाग की विभिन्न नर्सरियों से अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पेड एकत्रित कर, अगले हफते से पेड लगाने का कार्य शुरू करें। उन्होने बैठक में मौजूद डीडब्लयूईओ, डीईओ को सरकारी तथा निजी स्कूलों में स्थान पहचान कर पौधे लगाने, पब्लिक हेल्थ को टयूबवैल तथा पानी की टंकियों के आस पास, मार्किटिंग बोर्ड को मंडियों में, पुलिस विभाग को पुलिस लाईन में तथा सभी आईटीआई में जगह चिन्हित कर पौधे लगाने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि पौधों का रखरखाव करना संबंधित विभाग की जिम्मेदारी रहेगी।

कटारिया ने कहा कि संबंधित अधिकारी जिले के एनजीओ, रेजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशन व जिले के लोगों की भागीदारिता से जिले में अधिक से अधिक पौधे लगाने के लक्ष्य को पूरा करें। उन्होने कहा कि इस मुहिम में वन मित्रों, नेहरू युवा केंद्र तथा अन्य विभागों को भी जोडा जाए। उन्होने बताया कि पौधे लगाने से न केवल हम पर्यावरण को स्वच्छ बना सकते हैं बल्कि पेडों से हमें प्रचूर मात्रा में आक्सीजन भी मिलती हैं। कटारिया ने जिला के लोगों से इस मुहिम से जुडने व वन विभाग से पौधे लेकर और पौधारोपण कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की।

इस अवसर पर नगराधीश विश्वनाथ, जिला वन अधिकारी विशाल कौशिक, संयुक्त आयुक्त नगर निगम गौरव चैहान, एसीपी सुरेंद्र, कृषि विभाग के उपनिदेशक सुरेंद्र यादव, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की एक्सईएन निधि भारद्वाज, पीडब्लयूडी बीएंडआर, पंचायत विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम सहित अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का पहला स्कॉलर समिट 20 राज्यों के 2516 मेधावी छात्रों के सम्मान के साथ हुआ संपन्न

- सीयू स्कॉलर्स समिट 2025 के समापन पर कॉरपोरेट लीडर्स ने बताए सफलता के मंत्र और सफल जीवन के सबक

संवाददाता

मोहाली

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आयोजित तीन दिवसीय 'सीयू स्कॉलर्स समिट-2025' का पहला एडिशन अपनी प्रवेश-सह-छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 (सीयूसीईटी 2025) के शीर्ष प्राप्तकर्ताओं के सम्मान के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तीन दिनों तक चले इस समिट में शीर्ष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फर्मों के सीईओ, वाइस प्रेजिडेंट और इंडस्ट्री लीडर्स ने भाग लिया तथा 'नेविगेटिंग योर जर्नी टू करियर सक्सेस' विषय पर पैनल चचाओं में अपने विचार साझा किए और बताया कि वे उद्योग के तेजी से विकसित हो रहे परिदृश्य के बीच बदलती नौकरी की भूमिकाओं के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। भारत की नंबर 1 निजी यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित यह समिट प्रतिभाशाली छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों को सम्मानित करने और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 210 करोड़ रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करके मेधावी और प्रतिभाशाली छात्रों के सपनों को पूरा कर रही है। सीयू स्कॉलर्स समिट के पहले संस्करण में देश के 20 राज्यों से चयनित 2,516 छात्रों को 110 विभिन्न यूजी और पीजी स्ट्रीम्स में सम्मानित किया गया। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों में 918 छात्राएं भी शामिल थीं, जो शिक्षा में समानता को दशार्ता है।

स्कॉलर समिट के समापन समारोह में कई विशिष्ट अतिथि उपस्थिति रहे जिनमें टाइड प्लेटफॉर्म लिमिटेड के डिप्टी कंट्री मैनेजर और एसवीपी मैनेजर ऑपरेशंस कुमार शेखर, एरिक्सन, ऑटोमेशन सॉल्यूशंस के प्रमुख अभिषेक कुमार, 'मन कैप के सीईओ व मोटिवेशनल स्पीकर सोफी जहूर, सुप्रसिद्ध भारतीय अभिनेता व हास्य अभिनेता गुरप्रीत घुघी और प्रसिद्ध पंजाबी गायक एवं अभिनेता जसबीर जस्सी शामिल थे। इस दौरान, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स और 7 पूर्व छात्रों के साथ एक बातचीत सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों की उपयोगी जानकारी हासिल हुई। समिट के समापन दिवस पर छात्रों को संबोधित करते हुए, एरिक्सन के ऑटोमेशन सॉल्यूशन डिलीवरी के प्रमुख अभिषेक कुमार गुप्ता ने कहा, एआई अकल्पनीय गति से नौकरियों को अपने कब्जे में ले लेगा, लेकिन कुछ कौशल हमेशा हमारे साथ रहेंगे और रचनात्मकता ऐसा ही एक कौशल है जो आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सीखने जा रहे हैं। छात्रों के पास एक विजन होना चाहिए और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपको उस विजन को साकार करने के लिए सही मंच प्रदान करेगी। कॉरपोरेट जटिल समस्याओं के लिए सरल समाधान की तलाश करते हैं, इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें, यही आपको आगे ले जा सकता है। इंटरनेट को दुनिया में क्रांति लाने में 20 साल लगे, लेकिन आज इंटरनेट के बिना रहना मुश्किल है।

एसीबी रोहतक की टीम ने डिपो प्रबन्धक को तीस हजार रुपये नकद रिश्वत लेते दबोचा

संवाददाता

चंडीगढ़

एसीबी रोहतक ने 9 जून को भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी धर्मेन्द्र कटारिया, डिपो प्रबन्धक भारतीय खाद्य निगम, गोहाना, जिला सोनीपत को शिकायतकर्ता से 30,000/-रुपए (तीस हजार रुपये) नकद रिश्वत लेते हुए कार्यालय भारतीय खाद्य निगम, गोहाना जिला सोनीपत से रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ने एसीबी रोहतक को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि वह भारतीय खाद्य निगम, गोहाना में यू.डी.सी. क्लर्क के पद पर कार्यरत है। उसका तीन महीने पहले भारतीय खाद्य निगम, सफीदो जिला जींद से भारतीय खाद्य निगम, गोहाना का स्थानांतरण हुआ था। आरोपी धर्मेन्द्र कटारिया डिपो प्रबन्धक भारतीय खाद्य निगम, गोहाना जिला सोनीपत द्वारा अब उसका स्थानांतरण भारतीय खाद्य निगम बरोदा, सोनीपत का कर दिया। आरोपी धर्मेन्द्र कटारिया दोबारा उसका स्थानांतरण भारतीय खाद्य निगम बरोदा, सोनीपत से भारतीय खाद्य निगम गोहाना, सोनीपत में करने व उसके ओवर टाईम भत्ता पास करने की एवज में उससे 30,000/-रुपए (तीस हजार रूप्ये) नकद बतौर रिश्वत की मांग कर रहा है। इस शिकायत पर कार्यवाही करते हुए एसीबी, रोहतक ने आरोपी धर्मेन्द्र कटारिया डिपो प्रबन्धक भारतीय खाद्य निगम, गोहाना जिला सोनीपत को शिकायतकर्ता से 30,000/-रुपए नकद रिश्वत लेते हुए कार्यालय भारतीय खाद्य निगम, गोहाना जिला सोनीपत से रंगे हाथो गिरफ्तार किया है।

आईसर मोहाली में खगोल विज्ञान ओलंपियाड ओरिएंटेशन-कम-सिलेक्शन कैंप का आयोजन

संवाददाता

चंडीगढ़

अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड (IOAA) 2025 के लिए भारत की प्रतिनिधि टीम के चयन हेतु ओरिएंटेशन-कम-सिलेक्शन कैंप (OCSC) का आयोजन इस वर्ष IISER मोहाली में किया जा रहा है। यह प्रतिष्ठित कैंप होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र (HBCSE-TIFR), मुंबई द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, लेकिन इस वर्ष HBCSE स्वयं IOAA 2025 की मेजबानी कर रहा है, जिसके कारण चयन व प्रशिक्षण की ज़िम्मेदारी IISER मोहाली को सौंपी गई है।

इस कैंप का उद्देश्य देशभर से चयनित प्रतिभाशाली छात्रों को खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के सिद्धांतों व तकनीकों में प्रशिक्षण देना और उनकी समझ का आकलन करना है। चयनित छात्रों को व्याख्यान, ट्यूटोरियल, टेलीस्कोप सेटअप व संचालन, और रात्रिकालीन आकाशीय अवलोकन जैसे सत्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

भारतीय राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड के माध्यम से लगभग 500 छात्रों में से कुल 54 छात्रों का चयन OCSC के लिए हुआ, जिनमें से 37 छात्र इस बार डउरउ में भाग ले रहे हैं। ये छात्र ग्रुप ए (कक्षा 12) और ग्रुप बी (कक्षा 10 व 11) से शीर्ष प्रदर्शनकताओं में शामिल हैं।

OCSC के आयोजन में केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा, महेंद्रगढ़; थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पटियाला; IIT कानपुर; अशोका विश्वविद्यालय, सोनीपत; केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल, शाहपुर और IISER मोहाली के खगोलविदों की एक टीम ने सक्रिय भूमिका निभाई है। प्रशिक्षण सत्रों का संचालन इन संस्थानों के विशेषज्ञों के साथ-साथ रमन रिसर्च इंस्टिट्यूट, बेंगलुरु और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बेंगलुरु के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया।

OCSC के समापन पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली 5 सदस्यीय टीम की घोषणा 11 जून 2025 को प्रातः 9:30 बजे, IISER मोहाली के LH6, लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स में आयोजित समारोह में की जाएगी। इस अवसर पर अशोका विश्वविद्यालय, सोनीपत के प्रोफेसर दीपांकर भट्टाचार्य एक विशेष व्याख्यान देंगे। इसके पश्चात इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स (IAPT) द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और पदक प्रदान किए जाएंगे। OCSC में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों की भी घोषणा की जाएगी।

संक्षिप्त-समाचार

11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 345 प्रतिभागियों को योग प्रोटोकाल का करवाया अभ्यास

पंचकूला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में महानिदेशक आयुष विभाग हरियाणा संजीव वर्मा, आई0ए0एस0 के निदेर्शानुसार, जिला प्रशासन पंचकूला एवं आयुष विभाग के द्वारा 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। डॉ. दिलीप कुमार मिश्रा, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, पंचकूला की अध्यक्षता में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज जिला के हुडडा/आरडब्लयूए पंचकूला में 345 प्रतिभागियों को योग प्रोटोकाल का अभ्यास करवाया गया। सभी ने पूर्ण उत्साह से इस योग प्रोटोकॉल का अभ्यास किया। इसी कार्यक्रम में आयुष विभाग के चिकित्सकों ने भाग लेते हुए हुडडा/आरडब्लयूए पंचकूला को लगभग 50 पौधें भी वितरित किए गए। योग प्रोटोकाल का आंरभ प्रार्थना मंत्र के उच्चारण से किया गया तदोपरांत योग क्रियाओं का अभ्यास करवाते हुए इन यौगिक क्रियाओं द्वारा होने वाले लाभों की भी जानकारी दी गई।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र सिविल हस्पताल सेक्टर 6 में लगाया गया कैंप

पंचकूला। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिले के सभी सरकारी स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों, में 0-18 वर्ष के बच्चों का हेल्थ चेकअप राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा किया गया। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जन्मजात दोष, जन्मजात बीमारिया व कमी, बचपन की बीमारी, विकासात्मक देरी और विकलांग बच्चों की स्क्रीनिंग की जाती है और अलग-अलग जन्मजात दोष, जन्मजात बीमारियों व कमी के बच्चों को मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र सिविल हस्पताल सेक्टर 6 में रेफर किया गया। यहाँ पर स्पेशलिस्ट व प्रोफेशनल डाक्टरों की टीम द्वारा बच्चों का इलाज किया जाता है। जन्मजात दोषों के बच्चों के इलाज के लिए तृतीयक देखभाल केंद्र (पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, फोर्टिस अस्पताल मोहाली, जीएमसीएच 32 स्माइल ट्रेन क्लिनिक सेक्टर 34, चंडीगढ़ में भेजा जाता है। जिला पंचकूला में 5 टीमो को लगाया गया है जो की सभी सरकारी स्कूलों व आंगनबाड़ी में 0-18 साल के बच्चो का चेक-अप करते है। आंगनबाड़ीयों में साल में 2 बार व स्कूलों में 1 बार चेक अप के लिए टीम जाती है। जिला पंचकूला में कुल 534 आंगनबाड़ी व 422 स्कूल है। सिविल हस्पताल सेक्टर 6 में आज राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र में सर्जन पंचकूला डॉक्टर मुक्ता कुमार व उप सिविल सर्जन पंचकूला डॉक्टर शिवानी की अध्यक्षकता में विकलांग बच्चों के लिए कैंप लगाया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी, जिला बाल सुरक्षा अधिकारी, क्योर इंडिया से अधिकारी के साथ-साथ बच्चे व उनके माता पिता भी मौजूद रहे।

राजवंत राय शर्मा को विधान सभा हलका खरड़ का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया

मोहाली। पंजाब प्रदेश कांग्रेस की तरफ से वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में 117 विधानसभा हलकों के कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। इनकी नियुक्ति से पहले सभी हलकों का पार्टी प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और सीनियर नेताओं ने दौरा किया था और सभी हलकों से फीडबैक लिया गया है। इसके बाद अब तैनाती की गई है। वहीं, पार्टी की कोशिश है कि जो लंबे समय से लोग पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उन्हें ही कमान सौंपी जाएगी। पार्टी के महासचिव संदीप संधू की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। इस दौरान मोहाली से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजवंत राय शर्मा को विधानसभा हलका खरड़ का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है।

प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्याओं का समाधान करें अधिकारी: उपायुक्त मोनिका

- समस्याओं के समाधान करने में कोताही की कोई गुंजाईश नही

संवाददाता

पंचकूला

उपायुक्त मोनिका गुप्ता की अध्यक्षता में लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपायुक्त ने जिलावासियों की समस्याओं को सुना और उनको प्राथमिकता के आधार पर समाधान के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए। सोमवार को समाधान शिविर में 18 शिकायतें आई, जिनके निपटाने के लिए सम्बन्धित विभाग को निर्देश दिए। शिविर में उपायुक्त ने मोगीनंद के ग्रमीणों की सन 2022 का पास हुआ टयूबवैल अभी तक न लगने की शिकायत पर एक्सईएन, पब्लिक हेल्थ को मामले की 2 दिन में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने बताया कि पंचकूला जिला में तीन स्थानों पर समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शहरी लोगों की समस्याओं को नगर निगम के सेक्टर-4 स्थित कार्यालय में सुना जा रहा है। वहीं कालका विधानसभा के लोगों के लिए एसडीएम कार्यालय कालका में समाधान शिविर लगाया जा रहा है। इसके अलावा जिला स्तर पर लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर आयोजित हो रहा है। उपायुक्त ने बताया कि इन समाधान शिविरों में परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, जमीन की रजिस्ट्री, शहरी निकाय विभाग से एनडीसी लेने, नक्शे की मंजूरी, पेंशन, राशन कार्ड एवं सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, अपराध, बिजली-पानी संबंधी आदि शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है।

इस अवसर पर एसडीएम चंद्रकांत कटारिया, नगराधीश विश्वनाथ, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जिला विकास एवं पंचायत विभाग, आयुष विभाग, जिला परिषद, पीएचईडी विभाग, एमआई काडा विभाग, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग,, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, मत्सय विभाग, पुलिस विभाग, माईनिंग, पीडब्लयूडी बीएंड आर, सिंचाई विभाग, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, यूएचबीवीएन, नगर निगम कालका व पंचकूला के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

आल इंडिया मेयर काउंसिल की 115 एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक पंचकूला में 15 और 16

पंचकूला। आल इंडिया मेयर काउंसिल की 115 एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक पंचकूला में 15 और 16 जून को होगी। इस बैठक में देश भर से अलग-अलग शहरों के मेयर भाग लेंगे और अपने विचार साझा करेंगे। अमरावती एंक्लेव में होने जा रही इस मेयर कान्फ्रेंस का आयोजन पंचकूला के महापौर कुलभूषण गोयल द्वारा किया जा रहा है। कुलभूषण गोयल ने बताया कि माधुरी अतुल पटेल महापौर बुरहानपुर अध्यक्ष है। उमाशंकर गुप्ता राष्ट्रीय महासचिव हैं। प्रोमिला पांडे कानपुर मेयर, सुषमा खरकवाल लखनऊ मेयर, रेनू बाला गुप्ता करनाल मेयर पदाधिकारी हैं। इस बैठक में लगभग 45 से अधिक मेयर भाग लेंगे। इस मेयर कान्फ्रेंस का शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। उनके साथ स्थानीय शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल विशेष अतिथि रहेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को भी निमंत्रण दिया गया है। इस बैठक में प्रमुख तौर पर देवास में हुई पिछली बैठक के बारे में चर्चा होगी।

खाद्य आपूर्ति विभाग के उप निरीक्षक को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार

संवाददाता

चंडीगढ़

एसीबी की अम्बाला टीम द्वारा सोमवार को आरोपी मनोज कुमार, उप निरीक्षक खाद्य एंव आपूर्ति विभाग, बराडा को शिकायतकर्ता से 21,000/-रू. नकद बतौर रिश्वत राशी लेते मार्किट बराडा जिला अम्बाला से रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया व आरोपी के विरूद्ध अभियोग संख्या 19 दिनांक 9.6.2025 धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 व 308 (2) बी.एन.एस. 2023 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला में दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने एसीबी अम्बाला को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उसकी पत्नी के नाम सरकारी राशन डिपो है। यह डिपो जिला खाद्य एंव आपूर्ति विभाग बराडा के नियन्त्रण में है। कुछ दिन पहले वह खादय एंव आपूर्ति विभाग बराडा में तैनात उप निरीक्षक मनोज कुमार से वह मिला जिसने उससे दबाब बनाकर उससे 10,000/-रू. ले लिये।

दिनांक 4.6.2025 को उप निरीक्षक मनोज कुमार उपरोक्त द्वारा उसको फोन किया तथा उसे मिलने के लिये कहा। इस पर जब वह आरोपी उपरोक्त से मिला तो उसने उससे डिपो चलाने के लिये उससे 6600/-रू. स्वंय के लिये व 20,000/-रू. उच्च अधिकारियों के लिये बतौर कमीशन के रूप में कुल 26,600/-रू. रिश्वत की मांग की गई। इसके पश्चात उसके द्वारा इतनी रकम न होने बारे विचार विमर्श उपरान्त आरोपी द्वारा कुल 21,000/-रू. बतौर रिश्वत लेने बारे सहमति दी गई। एसीबी प्रमुख ने आमजन से अपील करते हुये अनुरोध किया है, कि यदि काई सरकारी कर्मचारी/अधिकारी उनके सरकारी कार्य करने की एवज में उनसे रिश्वत की मांग करता है तो इसकी सूचना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा के टोल फ्री न. 1800-180-2022 व 1064 पर दें।

सराहनीय

30 राज्यों के 646 अस्पतालों में लागू, 6,444 छात्र स्वयंसेवी जुड़े

पीजीआई की 'परियोजना सारथी' को मिला देशव्यापी विस्तार

संवाददाता

चंडीगढ़

- 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1,467 अस्पतालों में अवधारणा को मंजूरी

पीजीआई द्वारा 5 मई, 2024 को शुरू की गई अस्पताल नेविगेशन और रोगी सहायता की अभिनव पहल 'परियोजना सारथी' ने अब 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी पहुंच बना ली है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा युवा मामले और खेल मंत्रालय के संयुक्त समर्थन से 'सेवा से सीखें - अस्पतालों में अनुभवात्मक अधिगम कार्यक्रम' के तहत 1,467 अस्पतालों को इस पहल में शामिल किया गया है, जिनकी सूची पोर्टल पर उपलब्ध है। सोमवार को पीजीआई के निदेशक प्रो. विवेक लाल ने इस सफलता पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि रोगियों को अस्पताल की जटिलताओं से मुक्त कराने और युवाओं की ऊर्जा को समाज सेवा की ओर मोड़ने के उद्देश्य से परियोजना सारथी की शुरूआत की गई थी। आज यह एक अनोखा सामुदायिक मॉडल बन चुका है। इसका मकसद अस्पतालों में रोगियों और उनके परिचारकों को सही मार्गदर्शन और सहारा देना है, साथ ही छात्रों को सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने का मौका देना है, जिससे उनमें सेवा और करुणा की भावना विकसित होती है।

प्रो. लाल ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में इस परियोजना की परिकल्पना की गई थी। यह पहल अब एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुकी है। मंत्रालयों के समर्थन से यह न केवल अस्पतालों की चुनौतियों को कम कर रही है, बल्कि एक जिम्मेदार युवा पीढ़ी को तैयार कर रही है। केवल पीजीआई में ही 50 हजार से अधिक स्वयंसेवी घंटों का योगदान दर्ज किया गया है।

इसी उत्साह को साझा करते हुए पंकज राय, उपनिदेशक पीजीआई ने बताया कि पोर्टल पर पीजीआई की अवधारणा पर आधारित ईएलपी (अनुभवात्मक अधिगम कार्यक्रम) को देशभर के 1,467 अस्पतालों में मंजूरी मिली है। इनमें से 17 सितंबर 2024 से 31 मई 2025 के बीच 551 अस्पतालों में इसे लागू किया जा चुका है, जबकि 95 अस्पतालों में यह प्रक्रिया जारी है। इनमें से 81 अस्पताल स्थायी ईएलपी के रूप में कार्यरत हैं। कुल मिलाकर, देशभर में 6,444 छात्र स्वयंसेवी इस पहल में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

रोगियों को जल्द इलाज दिलाने में मददगार

उन्होंने बताया कि शुरूआत में पीजीआई में रोगी सहायता के लिए इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरूआत की गई थी। इसके तहत शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े छात्र स्वयंसेवी अस्पतालों में मरीजों को नेविगेशन में मदद करते हैं। पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में ही 18 संस्थानों के 816 छात्रों ने 50,340 घंटे से अधिक सेवा दी है, जिससे मरीजों के औसत इंतजार समय को 4.2 घंटे से घटाकर 2.8 घंटे कर दिया गया है। इससे रोगियों और उनके तीमारदारों की संतुष्टि बढ़ी है और अस्पताल स्टाफ की कार्यक्षमता भी बेहतर हुई है।

इन राज्यों और केंद्रों में यह योजना है लागू

परियोजना सारथी की यह सफलता अब देशव्यापी आंदोलन में बदल चुकी है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के अनुसार, जिन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू या आंशिक रूप से लागू किया गया है, उनमें अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। इस राष्ट्रीय विस्तार के साथ, 'परियोजना सारथी' आने वाले समय में और भी अधिक अस्पतालों तक पहुंचेगी।

पंचकूला समर कार्निवाल में आइफिल टावर से लेकर झूलों ने किया आकर्षित

संवाददाता

चंडीगढ़

पंचकूला के सेक्टर-5 स्थित हुडा ग्राउंड में पंचकूला समर कार्निवाल का भव्य शुभारंभ हुआ। इस भव्य आयोजन को दिल्ली इवेंट्स द्वारा आयोजित किया गया है, जो पूरे एक महीने तक, 6 जुलाई 2025 तक शहरवासियों के लिए खुला रहेगा। यह कार्निवाल गर्मियों की छुट्टियों में मनोरंजन, खरीदारी और सांस्कृतिक अनुभवों का एक अनोखा संगम लेकर आया है। इस अवसर पर दिल्ली इवेंट्स के प्रबंधन सदस्य रवि सिंह ने कहा कि हमारा उद्देश्य पंचकूला और आसपास के लोगों को एक ऐसा अनुभव देना है जहाँ मनोरंजन, संस्कृति और कला सब एक साथ हों। यह कार्निवाल सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि परिवारों के लिए गर्मियों की यादगार शामों का उत्सव है। हम चाहते हैं कि लोग यहां आएं, सेल्फी लें, शॉपिंग करें, खाना खाएं और अपने परिवार के साथ आनंद लें। खास बात यह है कि स्कूल और कॉलेज के छात्रों को इस कार्निवाल के लिए विशेष छूट दी जाएगी, ताकि युवा वर्ग भी पूरे उत्साह से इसमें भाग ले सके।

कार्निवाल में हर आयु वर्ग के लिए ढेरों आकर्षण मौजूद हैं। सेल्फी जोन में दर्शक विश्व प्रसिद्ध ट्विन टावर्स और आइफि ल टावर की भव्य प्रतिकृतियों के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं, वहीं बच्चों और परिवारों के लिए रोमांचक डायनासोर पार्क और रहस्यमयी मैजिकल विस्परिंग गार्डन खास आकर्षण का केंद्र हैं। इसके अलावा, हस्तशिल्प और फूड स्टॉल्स में गुजरात के पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट, सहारनपुर के सुंदर लकड़ी के फर्नीचर, टेराकोटा व खुरजा की क्रॉकरी, और पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। मनोरंजन के शौकीनों के लिए 15 से अधिक झूले लगाए गए हैं, जो बच्चों और युवाओं को रोमांच और आनंद से भर देते हैं। आयोजकों द्वारा कार्निवाल में सुरक्षा, साफ-सफाई और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है ताकि हर आने वाले दर्शक को एक सुरक्षित और आनंददायक अनुभव मिल सके। आयोजकों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह कार्निवाल शहरवासियों के लिए गर्मियों की सबसे बड़ी आकर्षण बनकर उभरेगा।